SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 27 ● अंक : 27 ● नई दिल्ली ● 23 से 31 जुलाई 2024 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

आप नेता संजय सिंह का बीजेपी और एलजी पर तीखा वार, बोले- सीएम केजरीवाल को लेकर झूठ फैला रही बीजेपी

सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगा प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं, सरकार तुरंत वापस ले निर्णय : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह जारी एक कथित आधिकारिक आदेश का हवाला देते हुए रविवार को दावा किया कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे और राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों व इनके (भाजपा सरकार) अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। बसपा प्रमुख ने सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है जबकि कई बार प्रतिबन्धित रहे आरएसएस की गतिविधियां राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। मायावती ने इस निर्णय को अनुचित बताते हुए इसे तुरन्त वापस लेने की मांग की है। इससे पहले रविवार को, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है। उक्त आदेश में कहा गया है, ''उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए।

नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- 4 मई से पहले लीक हुए होंगे पेपर; आज फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली । नीट यूजी मामले में आज सोमवार (22 जुलाई) को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अब अदालत मंगलवार (23 जुलाई) को सुनवाई जारी रखेगी. इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे. जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर कब मिले, ये साफ नहीं है. दरअसल, एक सवाल के 2 संभावित जवाब से उपजे भ्रम का कुछ उम्मीवारों ने विरोध किया. इन लोगों ने कहा कि जिन बच्चों ने कोई एक जवाब दिया, उन्हें 4 अंक मिले. जिन्होंने भ्रम के चलते छोड़ दिया, उन्हें शून्य मिला. इसके चलते रैंकिंग बदल गई. सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक से आज ही 3 विशेषज्ञों की कमिटी बना कर सही जवाब तय करने को कहा. अब आईआईटी आज दोपहर 12 बजे जवाब देगा. उसके बाद सुनवाई फिर शुरू होगी.

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने लाल बिहारी यादव, जासमीर अंसारी उप नेता बने

लखनऊ । समाजवादी पार्टी ने यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। वहीं, मो. जासमीर अंसारी उप नेता बनाए गए हैं। इसी तरह किरनपाल कश्यप को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है जबकि आशुतोष सिन्हा को विधान परिषद का सचेतक बनाया गया है। बता दें कि लाल बिहारी यादव विधान परिषद में सपा दल के नेता भी रहे हैं लेकिन अभी तक सपा के पास नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक सदस्य संख्या नहीं थी। पांच मई को रिक्त हुए 13 पदों के चुनाव में सपा को तीन सीटें मिलीं। अब विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या 10 हो गई है, जो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या के बराबर है। उच सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए लाल बिहारी यादव कोर्ट भी जा चुके हैं इसलिए पार्टी ने यह जिम्मेदारी उन्हें को ही देने का फैसला किया है।

रामपुर में प्राइवेट व रोडवेज बस की आमने-सामने भिड़ंत, तीन की मौत और 26 घायल

लखनऊ। हरिद्वार से यात्रियों को लेकर सोमवार जमुनहा वापस लौट रही प्राईवेट बस की रामपुर में निगम की बस से आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में जमुनहा तहसील क्षेत्र निवासी तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि 26 लोग घायल हो गए। जिन्हें आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, घटना की सूचना के बाद परिजन निजी साधनों से घटनास्थल को रवाना हो गए। जमुनहा तहसील क्षेत्र से प्राइवेट बस यूपी 70 बीटी 0592 बुक कराकर 49 लोग बुधवार शाम शांतिकुंज हरिद्वार गए थे। जहां से सभी सोमवार को वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही बस रामपुर जिले के थाना मिलक नगर हाईवे स्थित भैरव बाबा मंदिर पहुंची तभी सामने से आ रही साहिबा बाग डिपो की बस यूपी 32 एमएन 8147 से आमने सामने भिड़ंत हो गई। करीब चार बजे सुबह हुए हादसे के वक्त बस में सवार सभी लोग सो रहे थे। टक्कर काफी तेज होने के कारण रोडवेज बस चालक सहित प्राईवेट बस में सवार मल्हीपुर थाना क्षेत्र के वीरगंज बाजार निवासी मनोहर मौर्या (60) पुत्र स्वामी दयाल, कथरा बाजार निवासी जगदीश गुप्ता (45) पुत्र सुंदर लाल गुप्ता व हरीराम विश्वकर्मा (60) पुत्र छोटे की मौत हो गई। जबकि 26 लोग घायल हो गए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रधानमंत्री ने 10 साल तक देश का गला घोंटा, अब खुद को लोकतांत्रिक साबित करें : कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर विपक्ष को लेकर ''अशोभनीय टिप्पणी की, जबकि उन्होंने 10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज दबाई जिसकी सजा जनता ने हालिया लोकसभा चुनाव में उन्हें दी। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को ''मोदी सरकार शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढंकने के लिए संसद का 'दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सभी राजनीतिक दलों से देश के प्रति समर्पित होकर संसद का उपयोग करने का आह्वान किया। संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले सत्र का उल्लेख किया और कहा, ''140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म दिया,

उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है।

खेड़ा ने एक बयान में कहा, '' जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज़ दबाई, वो आज प्रतिपक्ष के आवाज उठाने पर रुदन करता हुआ बेहद कमजोर दिख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिपक्ष पर अशोभनीय टिप्पणी के साथ आज मानसून सत्र की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री का ढाई घंटे तक गला घोंटा। उन्होंने दावा किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 साल के उनके अन्याय काल में पूरे देश का दम घोंटा गया, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी है। प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि वो बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं, दो दलों के सहयोग से चलने वाली राजग सरकार के एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं।

उन्हें ''मोदी सरकार शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। उनका कहना था, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मरण कराना उचित होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त देश के 32 लाख छात्रों की आवाज को दबाने और उनके साथ आपकी सरकार के अन्याय के खिलाफ देश का उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है। खेड़ा ने कहा, ''आप (मोदी) जब अपने अहंकार और झूठ से लबालब भाषण दे रहे थे तो आपको बताना जरूरी होगा कि देश के 15 से अधिक अग्निवीर देश के लिए प्राणों की आहुति का सपना अपने दिल में रख कर आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके है। उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये भाषण दे रहे थे, तब देश के 50 करोड़ किसान अपने खेत और अपनी खेती को बचाने के लिए ''के हर दमन, हर अत्याचार को सहते हुए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आपने ढाई साल से गला घोंट रखा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''आपने सही कहा प्रधानमंत्री जी, संसद देश के लिए है। वो किसी राजा का दरबार नहीं है। लिहाजा प्रतिपक्ष वहां देश के युवाओं, किसानों, जवानों,मजदूर, महिलाओं, पिछड़ें, दलितों, आदिवासियों और गरीबों के दर्द को आवाज़ संसद में उठाने को मजबूर है।

मुंबई के कई इलाकों में 24 घंटे में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज, एनडीआरएफ तैनात

मुंबई। (वेबवार्ता) मुंबई में कई स्थानों पर सोमवार को सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गयी, जिससे कल्याण और ठाकुर्ली स्टेशन के बीच व्यस्त समय के दौरान लोकल ट्रेन सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित हुईं। सुबह छह बजे से सात बजे के बीच महज एक घंटे में कुछ इलाकों में 34 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दावा किया कि शहर में स्थित स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) ने सुबह आठ बजे तक 24 घंटे के दौरान कई स्थानों में 200 मिलीमीटर से अधिक की बारिश दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश तथा समुद्र में ऊंची लहरें उठने के पूर्वानुमान के बीच शहर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के तीन दल तैनात किए गए हैं।

हम नीट का मुद्दा उठाते रहेंगे, राहुल बोले- सरकार पर दबाव बनाएंगे

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी में कथित अनियमितता का मुद्दा संसद के भीतर उठाते रहेंगे तथा सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''शिक्षा मंत्री जी को नीट के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय और प्रधानमंत्री की बात की, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि वो नीट

के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं? उनका कहना था, ''देश के युवाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। इससे पहले, राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट में कथित अनियमितता के विषय को लेकर सोमवार को सदन में सरकार पर प्रहार किया और दावा किया कि देश के करोड़ों छात्रों एवं देशवासियों को ''इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक 'फ्रॉड (धोखे वाली) है तथा जिसके पास पैसा है वह इस पूरी प्रणाली को खरीद सकता है। गत पांच मई को 23.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।

सम्पादकीय

गारंटी है, पुलों के गिरने की गारंटी है

हमारे देश की खासियत यह है कि मौसम कोई भी हो, लोग मौसम की मार से मरना नहीं छोड़ते हैं। जब गर्मी अधिक पड़ रही थी, ताड़ब-तौड़ लू चल रही थी, तापमान पचास डिग्री को छू रहा था, लोग गर्मी गर्मी से मर रहे थे और हम प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश आए। सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि जरा शांत हो जाएं और इंद्र देव आ जाएं। और अब इंद्र देवता आ गए हैं, बरस रहे हैं, तो भी हमें चैन नहीं है। हमारा मरना अब भी जारी है। बारिश में लोग मरते हैं, नदियों के उफान से, बांध बह जाने से, बाढ़ आने से, पुलों के टूट जाने से, पहाड़ों के दरक जाने से। शहर तो हमने ऐसे बना दिए हैं कि वर्षा ऋतु में थोड़ी सी बारिश पड़ी नहीं कि हर शहर वैनिस बन जाता है। केवल उदयपुर ही नहीं, हर शहर झीलों का शहर बन जाता है। बारिश के बाद सड़कों पर निकलो तो ऐसा लगता है कि बाधा दौड़ में हिस्सा ले रहे हों या फिर स्टीपल चेज़ खेल रहे हों। अगर गाड़ी में सवार हो तो सड़कों पर रोलर कॉस्टर का मज़ा आ जाता है। यह सब देश की सरकारों ने किया है। देश का इतना विकास किया है कि विकास विनाश प्रतीत होने लगा है। यह विनाश सरकार योजना बना कर करती है। इस योजनाबद्ध विकास की वजह से ही इतना योजनाबद्ध विनाश हो रहा है। यह विकास हमने पहाड़ों पर भी किया है। पहाड़ों का तो विकास कर उन्हें पूरा प्लेन बनाने की योजना है। बिहार में जो इतने पुल गिर रहे हैं, यह भी सरकार जी की विकास योजना के तहत ही गिर रहे हैं। पुल गिरने का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जब पुल गिरता है तो दोबारा बनता है। नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों, सभी की जेब दूसरी बार भरती है। दूसरी बार ही नहीं, बार बार गिरे तो बार बार भरती है। तीसरी, चौथी, पाँचवी बार भरती है। हंसी-मज़ाक अलग, सच्ची बात तो यह है कि पुल गिरने से, सड़क टूटने से रोजगार का सृजन होता है। देश की जीडीपी बढ़ती है। एक ही पुल को, एक ही सड़क को बारम्बार बनाया जाए तो मजदूरों को बार बार दिहाड़ी मिलती है और उनके सुपरवाइजर को, ओवरसीयर और इंजीनियर को भी वेतन मिलता है। कुछ मजदूर तो किसी पुल या सड़क के किनारे ही बस जाते हैं। उन्हें इन्हें बनाते वक्त ही पता होता है कि यह पुल, यह सड़क बार बार टूटेगी और हमें यहीं बार बार रोजगार मिलेगा। पुलों के बार बार गिरने और बार बार बनाने से सिर्फ रोजगार का ही सृजन नहीं होता है, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, सरिया आदि जैसी चीजों की खपत भी बढ़ती है। इनको बनाने वाले उद्योग धंधे उन्नति करते हैं। देश प्रगति के पथ पर चलता है। विद्युत उद्योग को ए ग्रेड के नाम पर सी ग्रेड कोयला सप्लाई करने वाले उद्योगपति जब सरकार को सीमेंट सप्लाई करते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। विज्ञापन बनाते हुए तो ऐसा सीमेंट देते हैं कि छत पर हाथी भी चढ़ जाए तो भी कुछ न हो पर जब उस सीमेंट से पुल बनता है तो ऐसा बनता है कि आदमी के चलने से भी गिर जाता है।

हिंदू पानी, मुसलमान पानी!

अब बताइए, योगी जी की पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिले में जो आर्डर निकाला था कि ठेले-खोमचे वालों से लेकर ढाबे-रेस्टोरेंटों तक, कांवड़ियों के रास्ते पर पड़ने वाले खाने-पीने के सामान के सभी दुकानदारों को मालिक के नाम वाले साइन बोर्ड लगाने चाहिए, जिससे कांवड़ियों को नाम देखकर ही दुकान के धर्म का पता चल जाए, तो सेकुलरवालों ने शोर मचा दिया कि यह तो धर्म के हिसाब से भेदभाव करना है। कोई पीछे अंगरेजों के टैम में चला गया कि यह तो विदेशी राज के हिंदू पानी- मुसलमान पानी, हिंदू चाय- मुसलमान चाय वगैरह की वापसी है, तो कोई हिटलर के टैम की जर्मनी तक चला गया, कि यह तो यहूदियों की दुकानों पर पीले सितारे लगाकर, दूर से ही पहचान कराए जाने की नकल है। इतनी मोटी सी बात इन सवा चतुरों को दिखाई नहीं दी कि अगर योगी जी की पुलिस को हिंदू-मुसलमान ही करना होता, तो सिर्फ कांवड़ियों के रास्ते पर ही यह हुक्म क्यों लागू होता? योगी जी की पुलिस यही हुक्म अगर सारे जिले में ठेले-खोमचे, ढाबा-रेस्टोरेंट वालों पर बल्कि सिर्फ खाने-पीने के सामान वाले ही क्यों, हर तरह की दुकानों, दफ्तरों वगैरह पर भी लागू करा देती, तो क्या कोई उसका हाथ पकडने वाला था? कोई नीतीश, कोई चिराग, कोई चंद्रबाबू, कोई अल्पसंख्यक अधिकार आयोग, कोई मानवाधिकार आयोग, कोई अदालत, कोई भी? फिर भी उसने सब दुकानों, दफ्तरों को तो छोड़ ही दो, सब खाने-पीने के सामान वालों पर भी यह हुक्म लागू नहीं किया। हुक्म लागू किया तो सिर्फ कांवड़ियों के रास्ते पर पड़ने वाली रेहड़ियों, खोखों, दुकानों, ढाबों वगैरह पर। आखिर क्यों? क्योंकि इस हुक्म का हिंदू-मुस्लिम से कुछ लेना-देना ही नहीं है। इसके पीछे तो सिर्फ एक चिंता है--कांवड़ियों और उनकी कांवड़ की शुद्धता सुरक्षित रहे। बस कोई हिंदू कांवड़ियां किसी मुसलमान से, मुसलमान के छुए चाय-पानी वगैरह से, मुसलमान दुकानदार के गल्ले से निकले नोटों-रेजगारी वगैरह से, मुसलमान की दुकान की बैंच, स्टूल, कुर्सी मेज वगैरह से, छुआ न जाए; छुआने से अशुद्ध न हो जाए। उसकी कांवड़ का गंगाजल अपवित्र न हो जाए, जैसे दलितों के छुआने से हो जाते हैं। बस इतनी सी तो बात है--अशुद्ध को छुओ मत, अशुद्ध से छुआओ मत और अशुद्धो, तुम शुद्ध को छू मत लेना, वर्ना...। इसका भला हिंदू-मुस्लिम करने से क्या लेना-देना है। मुसलमान भी तो दूर से ही नाम देखकर हिन्दुओं के छुए से अपनी शुद्धता की हिफाजत कर सकते हैं। उन्हें भी अधिकार है, अगर मुसलमान कांवड़ नहीं ले जाते तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हिन्दू अपनी शुद्धता से समझौता क्यों करें? फिर भी पता नहीं कहाँ से सेकुलर वाले चले आए ठेलों पर ''ना हिंदू, ना मुसलमान, मोहब्बत की दुकान'' की तख्तियां लगवाने! फिर भी इन सेकुलर वालों ने मुजफ्फर नगर पुलिस के हुक्म पर इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि कमजोर दिल वाले भगवाइयों को भी डर लगने लगा था कि कहीं योगी जी, विरोधियों के शोर के आगे कमजोर न पड़ जाएं; कहीं पब्लिक के सामने मुजफ्फरनगर के पुलिस अफसरों के कान न खींच दिए जाएं कि लखनऊ के हुकुम के बिना, ऐसा हुकुम कैसे जारी कर दिया! बेचारे मुजफ्फर नगर के पुलिस अफसरों ने भी शोर से घबराकर जब यह कहना शुरू किया कि उनका हुक्म तो स्वैच्छिक था, जिसे नहीं जंचे नहीं भी मानेगा तो भी जेल थोड़े ही भेजा जाएगा; तब तो कमजोर दिल वाले भगवाइयों के दिल ही बैठ गए।

लोकसभा चुनाव की हार का घाव ताजा था। ऊपर से लखनऊ में चुनाव में हार की समीक्षा में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच, एक-दूसरे के सिर पर ठीकरा फोडने के चक्कर में सिर-फुटौव्वल और। बाकायदा मोदी-बनाम योगी की रस्साकशी। फिर भी जब बहुतों को लग रहा था कि हो न हो, इस बार तो योगी जी दब जाएंगे, तभी योगी जी ने अगली ही बॉल पर छक्का जड़ दिया। जो मुजफ्फर नगर से शुरू हुआ है, पूरी यूपी में होगा। खोमचे, ठेली, दुकान, रेस्टोरेंट, सब को बोर्ड पर धर्म की पहचान कराने वाला नाम लगाना होगा, जिससे दूर से देखकर ही खाने-पीने की चीजों के धर्म की पहचान हो जाए। कोई गलती से, गलत धर्म वाली किसी चीज से छू नहीं जाए। योगी जी की देखा-देखी, धामी जी ने भी उत्तराखंड में वही हुक्म जारी कर दिया है। इसी महीने उपचुनाव में पब्लिक ने उन्हें भी तो पटखनी लगायी है। पवित्रता की डिमांड बढ़ती गयी यों-यों पब्लिक ने लात लगायी भगवाइयों को। हिंदू , इन सेकुलरवालों की इस झूठी दलील में आने वाला नहीं है कि अगर कांवड़ियों के शाकाहार की शुद्धता की ही रक्षा की चिंता होती तो, शाकाहारी ढाबों/ रेस्टोरेंटों के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी लिखवाना काफी था। धर्म की पहचान कराते हुए मालिकों के नाम लिखाने की क्या जरूरत थी? पर बात शाकाहार-मांसाहार की है ही नहीं। उनकी शुद्धता को सिर्फ शाकाहार-मांसाहार तक सिकोड़ दिया जाए, यह हिंदुओं को मंजूर नहीं होगा। ऐसे तो कल को ये कहेंगे कि अलग शुद्ध शाकाहारी ढाबे की भी क्या जरूरत है, शाकाहार की शुद्धता को एक ही ढाबे में बगल के पतीले से बगल की मेज पर बैठकर, खाने तक सिकोड़ लो। पहले मंजूर हो सकता था, मोदी जी-योगी जी के भारत में यह सब नहीं चलेगा। अब हमारी शुद्धता का गैर-शाकाहारी को बंद ही कराने तक विकास होगा। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमारी शुद्धता, कम से कम छुआछूत की अपनी पुरानी परंपरा के पुनरुत्थान तक तो जानी ही चाहिए। अशुद्ध को अदृश्य बनाने का तकाजा करने वाली आला दर्जे की शुद्धता के लिए शायद, एक और कार्यकाल का इंतजार करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा! और हां ये दलित वगैरह छुआछूत के पुनरुत्थान पर यादा हल्ला नहीं मचाएं। यह न भूलें कि योगी जी-मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है कि दुकानों के बोर्डों पर जाति-प्रमाणपत्र नहीं लगवाए जाएंगे। ना भूलें कि जाटव पानी, मुसलमान पानी से कम अशुद्ध नहीं होता है।

ट्रंप ने मज़दूर वर्ग से और भी कई झूठे वादे किए

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, ने 18 जुलाई की आखिरी रात रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को संबोधित किया। उनका संबोधन अमेरिका में कामगारों के लिए अपीलों से भरा हुआ था, जो लोग ज़ो बाइडेन प्रशासन की कारगुज़ारी की वजह से गहरी आर्थिक निराशा का सामना कर रहे हैं (जिसका सामना वे पिछले प्रशासनों के दौरान भी करते आए हैं)। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के घरेलू पल्स सर्वेक्षण के अनुसार, 22 करोड़ 20 लाख से अधिक सर्वेक्षण उत्तरदाताओं में से अधिकांश (67 फीसदी) का दावा है कि पिछले सात दिनों में सामान्य घरेलू खर्चों का भुगतान करने में कठिनाई हुई है - कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि 2020 से किराने की कीमतों में लगभग 27 फीसदी की वृद्धि हुई है। ब्रेकथ्रू न्यूज़ के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, यूजीन प्यूरियर ने कहा कि श्रमिकों से रिपब्लिकन की अपील देश में समग्र राजनीतिक माहौल को बयां करती नज़र आती है। उन्होंने कहा, हम बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को श्रमिक वर्ग, कामकाज़ी लोगों के बारे में बात करते हुए देखते हैं, ट्रंप, जेडी वेंस और रिपब्लिकन भी श्रमिक वर्ग, कामकाज़ी लोगों, के बारे में बात करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी पार्टी श्रमिक वर्ग की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। अगर ये दो पूंजीवादी पार्टियाँ, जिनके पास सबसे व्यापक मतदान डेटा तक पहुँच है, सोचती हैं कि उन्हें अपने अभियान में, एक वर्ग के रूप में, श्रमिक वर्ग से अपील करनी है, भले ही यह एक धोखाधड़ी वाली अपील हो, यह पुष्टि करता है कि संयुक्त राय अमेरिका में वर्ग चेतना बढ़ रही है। जैसा कि ट्रेड यूनियनों और समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता से देखा जा सकता है। हालांकि, रिपब्लिकन की कामकाज़ी लोगों से की गई अपील ऐसी है जो उनकी कठिनाइयों को पहचानती है, लेकिन कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करती और किसी भी तरह से उनके वर्ग हितों को ख़तरे में डालती है। जैसा कि सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया, उनका दृष्टिकोण गलत सूचना देना, गलत तरीके से उन्हे प्रस्तुत करना, बलि का बकरा ढूँढना और राष्ट्रवादी अंधराष्ट्रवाद का ढोल पीटना है। ट्रंप ने कहा कि, हम किसी देश को हमारे यहां आकर हमारी नौकरियां छीनने और हमारे देश को लूटने नहीं देंगे। वे आते हैं और ऐसा करते हैं। वे हमारे देश को लूटते हैं। जिस तरह से वे अमेरिका में अपने उत्पाद बेचते हैं, वे खुद को अमेरिका में बनाते हैं, जो बहुत सरल है। वे इसका निर्माण अमेरिका में करें और केवल अमेरिका में उन्हे उत्पादित करें... अगर आप 20, 25 साल पीछे जाएं तो उन्होंने चीन और मैक्सिको जाकर हमारे ऑटो उद्योग का लगभग 68 फीसदी हिस्सा चुरा लिया है। विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां छीन ली है। हम उन सभी को वापस लाने जा रहे हैं। हम उन सभी को वापस लेने जा रहे हैं, उनमें से हर एक को वापस लेंगे। ट्रंप ने टैरिफ और सरकारी नियमों को उलटकर विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों को अमेरिका में वापस लाने का वादा किया है। मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाने की अपनी प्रतिबद्धता की शपथ लेते हुए, ट्रंप ने यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के अध्यक्ष, प्रमुख यूनियन नेता शॉन फेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने मुख्य रूप से फेन को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों को मैक्सिको में जाने की अनुमति देने के लिए दोषी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि, और अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं, तो समान सीमा पार मैक्सिको के बड़े कारखाने बन रहा है, जो अभी शुरू हुए हैं। इसलिए, हमारी सीमा पर अन्य सभी चीजें हो रही हैं, और वे चीन द्वारा कारें बनाने और उन्हें हमारे देश में बेचने के लिए बनाई जा रही हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स को ऐसा होने देने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के नेता को तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए और हर एक ऑटोवर्कर, यूनियन और नॉनयूनियन को, डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहिए क्योंकि हम कार निर्माण को वापस लाने जा रहे हैं और हम इसे तेजी से वापस लाने जा रहे हैं। विनिर्माण संयंत्रों के बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ में चले जाने का कारण स्पष्ट रूप से मजबूत यूनियन नेताओं की वजह से नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट लालच और अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि के कारण है जिसे पूंजीपति ग्लोबल साउथ में सस्ते श्रम से निकाल सकते हैं, यानी वैश्वीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जो पिछले कई दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रेरक शक्ति रही है। पिछले साल बिग थ्री ऑटो निर्माताओं, स्टेलेंटिस, फोर्ड और जनरल मोटर्स में सफल यूएडब्ल्यू हड़ताल की एक केंद्रीय मांग वास्तव में उन कारखानों को फिर से खोलना था जो ऑफशोरिंग और वैश्वीकरण के कारण बंद हो गए थे। अपने भाषण के दौरान, ट्रंप ने अमीरों के लिए टैक्स कटौती करने और मज़दूरों के पक्ष में नियमों में कटौती की अपनी विरासत का गर्व से बखान किया। जो अब तक की सबसे बड़ी टैक्स कटौती है। उन्होंने कहा कि, अब तक की सबसे बड़ी विनियमन कटौती है... हमने बहुत कुछ किया। हम बहुत कुछ करते हैं। ट्रंप पहले भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और जैसा कि उन्होंने गर्व से कहा, उनका रिकॉर्ड साबित करता है कि उनकी सच्ची वफादारी अति-धनवानों के साथ है, न कि मज़दूर वर्ग के साथ। 2017 में, ट्रंप ने अमीरों के लिए टैक्स कटौती शुरू की, जिसने अमेरिकी इतिहास में श्रमिकों से धनवानों के लिए धन के सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक की शुरुआत की ङ्क इस दौरान प्रभावी रूप से 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का धन हस्तांतरण हुआ। उन्होंने इसे कैसे प्रबंधित किया? ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 36 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी कर दिया था, और उचतम ब्रैकेट में आने वालों से आयकर की दर को 39.6 फीसदी से घटाकर 37 फीसदी कर दी थी, और 12 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लोगों को प्रियजनों को छोड़ी गई विरासत पर कोई भी टैक्स चुकाने से छूट दी थी। उन्होंने संकेत दिया कि वे अपने दूसरे कार्यकाल में इस पर और भी आगे बढ़ेंगे। हम कर्ज चुकाना शुरू करेंगे और करों को और भी कम करना शुरू करेंगे। हमने आपको सबसे बड़ी टैक्स कटौती दी है। हम इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। अपने भाषण के दौरान, ट्रंप ने घोषणा की कि वह संयुक्त राय अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ाकर जीवन संकट और ऊर्जा की बढ़ती लागत को संबोधित करेंगे। ट्रंप ने सम्मेलन हॉल में कहा, हम ड्रिल करेंगे, बेबी, ड्रिल करेंगे। ऊर्जा की लागत में कटौती करके, हम बदले में परिवहन, विनिर्माण और सभी घरेलू सामानों की लागत को कम कर देंगे। बहुत कुछ ऊर्जा से शुरू होता है। और याद रखें, हमारे पैरों के नीचे किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तरल सोना है। हम एक ऐसा देश हैं जिसके पास अपनी ऊर्जा के ज़रिए अपने भाग्य बनाने का अवसर है। हमारे पास यह है और चीन के पास यह नहीं है। रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए पर्यावरण नियमों को खत्म करने और स्वदेशी भूमि अधिकारों का उल्लंघन करने, संयुक्त राय अमेरिका में गैस और तेल के बेरोकटोक निष्कर्षण के बदले में श्रमिकों के लिए नौकरियों और लाभों का वादा करना कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने अपने 2016 के अभियान में विजयी रूप से घोषणा की थी, हम अमेरिकी ऊर्जा पर प्रतिबंध हटाने के लिए साहसिक कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं... और हम अपने खनिकों को फिर से काम पर लगाने जा रहे हैं। 2024 के रिपब्लिकन पार्टी के मंच से कहा गया- कि राष्ट्रपति ट्रंप के तहत, अमेरिका दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस का नंबर एक उत्पादक बन जाएगा - और हम जल्द ही अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन पर प्रतिबंध हटाकर और समाजवादी ग्रीन न्यू डील को समाप्त करके फिर से नंबर एक बन जाएंगे। अगर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी अपने कठोर कार्यक्रम को लागू करते हैं, तो न केवल पृथ्वी ग्रह को नुकसान होगा - बल्कि श्रमिकों को भी नुकसान होगा, जिन्हें रूढ़िवादी लोगों ने ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सुरक्षा मुहैया कराई है। ट्रंप ने कई तरह की नीतियों को लागू किया, जिससे संघीय सुरक्षा नियमों को कमजोर किया गया, जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन निरीक्षकों की संख्या में कटौती करना भी शामिल है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के टिप पर करों को समाप्त करने के प्रस्ताव के बारे में भी बहुत कुछ कहा, उन्होंने एक वेट्रेस के बारे में एक भ्रामक किस्सा सुनाया, जिससे उन्होंने इस नीति की आवश्यकता के बारे में बात की थी। ट्रंप को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी वेट्रेस के साथ एक सार्थक राजनीतिक बातचीत की थी।

आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, वे सलाहकारों को काम पर रखते हैं। वे उन्हें [लाखों] डॉलर देते हैं... मुझे अपनी जानकारी एक बहुत ही स्मार्ट वेट्रेस से मिली। यह लाखों डॉलर खर्च करने से बेहतर है। रिपब्लिकन पार्टी के मंच पर टिप्स पर कोई कर नहीं के संबंध में कहा गया है, हम लाखों रेस्तरां और आतिथ्य कर्मचारियों के लिए टिप्स पर टैक्स को समाप्त कर देंगे, और अतिरिक्त टैक्स कटौती का प्रयास करेंगे। टिप्स पर कोई टैक्स नहीं प्रशासन (ट्रंप का) में कितना अछा हो सकता है, जिसने टिप चोरी नियम लागू किया, जिससे मालिकों/नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की टिप को जेब में रखना आसान हो गया? या जिसने फ़ेडरल न्यूनतम वेतन में किसी भी वृद्धि का विरोध किया? ट्रंप ने अपने भाषण का अधिकांश हिस्सा उन नीतियों पर जोर देते हुए बिताया जो श्रमिकों को एक दूसरे से अलग करती हैं, जिसमें हाल ही में आए अप्रवासियों, विशेष रूप से वेनेजुएला और अल साल्वाडोर से आए अप्रवासियों और बाकी कामकाजी वर्ग के बीच एक बहुत ही महीन रेखा शामिल है। ट्रंप और रिपब्लिकन ने अब तक देश से अप्रवासियों के बड़े हिस्से को सामूहिक रूप से निकालने का वादा किया है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

कॉर्निया डैमेज होने के बाद दर्द में थीं जैस्मिन, अली ने हर मिनट पढ़ी दुआ

छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री जैस्मीन भसीन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई थी। अभिनेत्री की आंखों में चोट लग गई थी, जिसकी वह कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए पहने गए कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से अभिनेत्री की कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अभिनेत्री ने बताया कि यह खबर सुनकर उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने कैसे उनका साथ दिया था। अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी जैस्मीन भसीन ने अपने बॉयफ्रेंड अली गोनी के लिए एक खास पोस्ट किया है, जिसके कुछ दिनों पहले उन्होंने खुलासा किया था कि दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए पहने गए कॉन्टैक्ट लेंस के कारण उनकी कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गई थी। बता दें कि जैस्मीन ने हाल ही में खुलासा किया था कि लेंस पहनने के बाद उनकी आंखों में बहुत दर्द होता था। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जैस्मीन ने एक इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि वह कुछ भी देखने में असमर्थ थीं। अब अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जैस्मिन ने अली के साथ अपने कुछ बेहतरीन पलों का एक वीडियो साझा किया और आंख की चोट के कारण जब वह दर्द में थी, तब उनके साथ रहने के लिए अली को धन्यवाद दिया है। जैस्मिन ने यह भी बताया कि अली ने उनके लिए प्रार्थना की और हर समय उनके साथ थे। वीडियो में अभिनेत्री ने लिखा, पिछले कुछ दिन बेहद मुश्किल थे, दर्द और बिना किसी को देखे बहुत बुरा महसूस कर रही थी। बहुत-बहुत धन्यवाद अली मेरे साथ दिन-रात रहने के लिए, बल्कि मेरी आंखें बनने के लिए, मुझे मुस्कुराने और दर्द को भूलने की कोशिश करने और हर मिनट मेरे लिए दुआएं पढ़ने के लिए। ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बिग बॉस 14 फेम ने खुलासा किया कि 17 जुलाई को एक इवेंट के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद यह घटना हुई। अभिनेत्री को अचानक तेज दर्द होने लगा और समय के साथ यह बदतर होता गया।

एपी ढिल्लों के गाने में दिखेगी सलमान-संजय की जोड़ी, खत्म होगा 12 साल का इंतजार

लोकप्रिय इंडो-कनाडाई गायक एपी ढिल्लों के गानों को लोग खूब पसंद करते हैं और यही वजह है कि उनके नए गाने पर दर्शकों की नजर बनी रहती है। कुछ महीने पहले एपी ढिल्लों अपनी परफॉर्मेंस के दौरान गिटार तोड़ने के कारण चर्चा में आ गए थे और अब फिर एक बार एपी सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह नकारात्मक नहीं, बल्कि अच्छी खासी और लोगों को खुश करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपी ढिल्लों जल्द ही बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं सलमान खान और संजय दत्त के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों अभिनेता एपी के नए गाने में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सलमान खान के पनवेल स्थित फार्महाउस में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है। अगर संजय दत्त और सलमान खान, एपी ढिल्लों के गाने में दिखाई देते हैं तो दर्शकों को 12 साल बाद दोनों को साथ देखने का मौका मिलेगा। मालूम हो कि सलमान और संजय आखिरी बार सन ऑफ सरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में भाईजान ने कैमियो किया था। फिल्म में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सन ऑफ सरदार से पहले सलमान खान और संजय दत्त चल मेरे भाई, ओम शांति ओम और साजन समेत कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों ने टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस के पांचवे सीजन को भी साथ में ही होस्ट किया था। बता दें कि सलमान खान इन दिनों अपनी नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं और संजय दत्त सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग में। एपी ढिल्लों अपने अभी तक के करियर में कई चार्टबस्टर गाने बना चुके हैं। इनमें ब्राउन मुंडे, साडा प्यार, विद यू, दिल नू इंसेन, तेरे ते, वो नूर, डिजायर, फरार, टेकओवर, वॉर और टोक्सिक शामिल हैं। उनके गानों पर लोग जमकर नाचते हैं और अपनी वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं।

जब मधुबाला ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी, उन्हें धमकी भरे फोन आने के बाद सुरक्षा मुहैया कराई गई...

जुल्फिकार अली भुट्टो और दिलीप कुमार से लेकर बाल ठाकरे तक, ब्यूटी क्वीन मधुबाला ने अपनी खूबसूरती और मुस्कान से सभी को दीवाना बनाया। 14 फरवरी, 1933 को जन्मी मधुबाला का कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने का इरादा नहीं था।बचपन से ही उनके दिल में छेद था और डॉक्टरों ने उन्हें जितना हो सके आराम करने की सलाह दी थी। हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें फिल्मी दुनिया में धकेल दिया गया। अपनी किताब में फिल्म पत्रकार अजय कुमार शर्मा ने लिखा है कि मधुबाला के लिए ज्यादातर नए फिल्म कॉन्ट्रैक्ट उनके पिता अताउल्लाह खान द्वारा साइन किए जाते थे, जो बहुत जिद्दी और अड़ियल थे। उनके कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर सेट पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने वाला सख्त क्लॉज शामिल होता था। साल 1950 में आई फिल्म निराला में मधुबाला देव आनंद और मजहर खान के साथ प्रमुख भूमिकाओं में थीं। एक दिन, मजहर खान ने मधुबाला के अनुबंध में निर्दिष्ट खंड के बारे में जाने बिना कुछ मेहमानों को शूटिंग देखने के लिए आमंत्रित किया। जब मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान को मजहर खान के मेहमानों के बारे में पता चला, तो उन्होंने गुस्से में निर्देशक एम. सादिक से बात की। नतीजतन, मेहमानों को सेट पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, और फिल्म की शूटिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई। मजहर खान खुद मधुबाला के पास गए और अपने मेहमानों को अंदर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। मधुबाला ने जवाब दिया, अब्बा (पिता) जो कहेंगे, वही होगा। अन्यथा, मैं शूटिंग छोड़ दूंगी। इस कथन ने मजहर खान को बहुत आहत किया। हालांकि, इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई। कुछ पत्रकारों ने इस बारे में मधुबाला से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे उचित तरीके से बात नहीं की। अजय शर्मा ने लिखा कि इस घटना से पत्रकारों का गुस्सा भी फूट पड़ा। भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने मिलकर इंडो-पाक जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन का गठन किया और मूवी टाइम्स पत्रिका के संपादक बी.के. करंजिया को इसका सचिव नियुक्त किया। संगठन ने तय किया कि जब तक अताउल्लाह खान और मधुबाला दोनों पत्रकारों से माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक वे मधुबाला की तस्वीरें, उनकी फिल्मों के विज्ञापन या साक्षात्कार अपने अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं करेंगे। इस दौरान मधुबाला को धमकी भरे फ़ोन आने लगे, जिनमें उन्हें अगवा करने की धमकी देने वाले लोग शामिल थे। इन धमकियों से परेशान होकर मधुबाला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाक़ात की। जवाब में प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्हें निजी सुरक्षा गार्ड दिए गए, जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते थे।

विक्की कौशल को मंडे टेस्ट में पास कराने के लिए धर्मा का जुगाड़, एक टिकट खरीदने पर एक टिकट फ्री

विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म बैड न्यूज रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों को प्यार मिल रहा है। बैड न्यूज साल 2019 में आई फिल्म गुड न्यूज की सीक्वल है, लेकिन इस फिल्म की कहानी गुड न्यूज से काफी अलग है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म को और यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिल्म के मेकर्स एक नए ऑफर के साथ आए हैं। आइए जानते हैं धर्मा प्रोडक्शन किस तरह से विक्की कौशल की इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क अभिनीत फिल्म बैड न्यूज को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अछी शुरुआत की। वहीं सोमवार को भी फिल्म को दर्शकों का प्यार मिले इसलिए बैड न्यूज के मेकर्स ने एक टिकिट के साथ एक फ्री टिकिट देने की घोषणा की है। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की जबरदस्त केमिस्ट्री उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है। फिल्म के गाने दर्शकों के दिलो-दिमाग पर जादू चलाने में कामयाब रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विक्की कौशल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जादू चला पाएगी या नहीं। विक्की कौशल की फिल्म बैड न्यूज हेटेरोपेटरनल सुपरफेकंडेशन के ईर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म की कहानी विक्की, तृप्ति और एमी के आस-पास बुनी गई है। बैड न्यूज में तृप्ति सलोनी बग्गा और विक्की कौशल अखिल चड्ढा के किरदार में नजर आ रहे हैं। बैड न्यूज एक कॉमेडी फिल्म है जिसे यादातर दर्शकों ने एनटेरटेनिंग बताया है। वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू शुरुआत करती नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से धर्मा प्रोडक्शन ने एक टिकिट के साथ एक फ्री टिकिट का प्रलोभन देकर दर्शकों को सिनेमाहॉल तक लाने की योजना बना रही है। अब देखना दिलचप्स होगा कि उनकी यह योजना कितनी सफल होती है।

दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए राहत फतेह अली खान, पुलिस स्टेशन ले जाया गया

मशहूर गायक राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से रोका गया है। विमान में चढ़ने से रोकने के बाद उन्हें दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें दुबई पुलिस स्टेशन ले गई है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक,राहत फतेह अली खान के पूर्व मैनेजर और मशहूर शोबिज प्रमोटर सलमान अहमद ने दुबई में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। राहत विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए दुबई में आए थे। इस दौरान उन्हें दुबई एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। राहत ने कुछ महीने पहले एक विवाद के बाद अहमद को नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद से वह कई मौके पर गायक के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद राहत और अहमद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। गौरतलब है कि एफआईए ने इस साल जनवरी में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की जांच शुरू की थी। इससे पहले फरवरी में सलमान अहमद का एक वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वह बॉलीवुड के कुछ मशहूर सितारों के साथ-साथ राहत फतेह अली खान को धमकी देते नजर आ रहे थे। इस वीडियो में वह इन सितारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की चेतावनी भी देते दिख रहे थे। कहा जा रहा था कि इन कलाकारों ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, जिसके बाद वह इस वीडियो में उन कलाकारों के प्रति नाराजगी और निराशा जाहिर करते दिखे थे। इस दौरान वह इन कलाकारों पर अपमानजनक टिप्पणी करते और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते नजर आए थे। इस वीडियो में राहत फतेह अली खान के अलावा कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, सलीम-सुलेमान, मीका सिंह, आदित्य नारायण और आशा भोसले के नाम का जिक्र हुआ था। सलमान अहमद ने दुबई, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में संगीत कार्यक्रमों के लिए इन कलाकारों का प्रबंधन किया था। राहत फतेह अली खान की गिरफ्तारी की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कई सुपरहिट गाने गाए हैं।

टैक्सपयेर्स को आने वाले बजट से है महत्वपूर्ण सुधारों और राहत की उम्मीद

नई दिल्ली । आज बजट पेश होने वाला है। बजट से आम जनता के साथ रियल एस्टेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को कई उम्मीदें है। अगर बात करें टैक्सपेयर्स की तो उन्हें भी राहतों की उम्मीद है। बहुत से लोग आयकर छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा और विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी। रियल एस्टेट और शिक्षा जैसे प्रमुख सेक्टर में भी प्रोत्साहनों की आशा है। जहां रियल एस्टेट में आवास की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है तो वहीं एजुकेशन सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार की उम्मीद है। आगामी बजट की ओर देखते हुए, रियल एस्टेट सेक्टर कई महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद कर रहा है जो विकास और दक्षता को बढ़ावा देंगे। रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने से निवेश आकर्षित होगा और नियमों को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन में वृद्धि और प्रॉपर्टी लेनदेन के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों में कमी या पहली बार घर खरीदने वाले के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट से रियल एस्टेट में वृद्धि होगी। किफायती आवास की परिभाषा का विस्तार करके इसमें 75 लाख तक के घरों को शामिल करना, जिनका कॉरपोरेट एरिया 90 वर्ग मीटर हो, और सीएलएसएस योजना या इसी तरह की योजना का पुनः लॉन्च करना गृह खरीददारों को और अधिक लाभ देगा। रियल एस्टेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। चूंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान अगले साल 13 फीसदी तक पहुंचने वाला है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आगामी बजट इस सेक्टर के विकास को और आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा, रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देना सबसे ज़्यादा आगे की मांगों में से एक रहा है। इससे डेवलपर्स को अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण लेने और कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि

वह इस पर गौर करे और इस सेक्टर को और मज़बूत करने के लिए लाभकारी कदम उठाए। मुकुल बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोतियाज के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है और यह आवास की बढ़ती मांग से प्रेरित है। जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2024-25 के करीब पहुंच रहे हैं, सेक्टर के भीतर एक प्रमुख अपेक्षा एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को लागू करने के साथ-साथ उद्योग का दर्जा देना है। इन लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने से सेक्टर में नई गति आएगी। रियल एस्टेट स्टेकहोल्डर्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में हाउसिंग डिमांड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन और सुधार पेश किए जाएंगे। घर खरीदने वालों और डेवलपर्स के लिए बढ़े हुए कर लाभ इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आवास अधिक अफोर्डेबल बनेंगे और इकनोमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा अनूप गर्ग, डायरेक्टर यूनिनव डेवेलपर्स ने कहा कि टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा और डिस्पोजेबल आय में सुधार होगा। इस तरह के बदलावों से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी, खर्च करने की क्षमता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ग्रुप 108 के एमडी अमिष भूटानी के अनुसार बजट से हमें ही नहीं हर व्यक्ति को काफी उम्मीदें हैं। हमारी मांग है कि बजट में जीएसटी को कम किया जाए। सीमेंट, स्टील और एल्युमिनियम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। ऐसे में इसे कम किया जाना चाहिए। इससे लोगों को सस्ते घर मुहैया करवाने में मदद मिल सकेगी। भारत की जीडीपी में अभी रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान लगभग 8 फीसदी है, जबकि यूरोप में तकरीबन 40 फ़ीसदी और चीन में 30 फ़ीसदी है। भारत के विकास के लिए यहां भी इसे बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग के अनुसार 2030 तक भारत में रियल एस्टेट सेक्टर 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। जिसमें अफॉर्डेबल और लग्जरी हाउसिंग दोनों सेगमेंट में राहत दिया जाना चाहिए। जिसमें जीएसटी में छूट और ब्याज में राहत, लो इनकम हाउसिंग के साथ ही मिड इनकम हाउसिंग को भी मिलनी चाहिए। देश में कृषि के बाद सबसे यादा रोजगार देने के मामलों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान महत्वपूर्ण है। बजट को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार की पीएलआई स्कीम का लाभ लेने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की निवेश की सीमा को कम करके 25 करोड़ तक ले आएगी, क्योंकि इस सेक्टर में अधिकतर उद्यमी माइक्रो और स्मॉल है। निवेश की सीमा कम करने और सरकार के प्रोत्साहन से जहां नए उद्योगों को पनपने का मौका मिलेगा वहीं बेहतर कंपटीशन भी होगा। सरकार ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के प्रति अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता अंतरिम बजट के माध्यम से पहले ही दिखा दी थी।

देश के आठ शहरों में बनेंगे एयरबस के एच125 हेलीकॉप्टर, टाटा की पार्टनरशिप में बनेंगे एडवांस्ड विमान

नई दिल्ली । यूरोप की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस ने अपने एच 125 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के आखिरी चरण के लिए भारत के आठ शहरों को चुना है. कंपनी इन शहरों में दूसरे प्लांट यानी चौथा असेंबली लाइन को खोलने का प्लान बना रही है. इसके लिए एयरबस ने भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप भी की है. खास बात ये है कि अगले कुछ दिनों में ही कंपनी के पहले असेंबली लाइन का उद्घाटन होना है. इसके बाद यहां पर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा. मामले पर जानकारी देते हुए एयरबस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन Olivier Michalon ने बताया है कि हमने फिलहाल भारत में आठ ऐसे शहरों को चिह्नित किया है जहां पर आखिरी असेंबली लाइन को खोलने पर विचार किया जा रहा है. अभी फिलहाल कंपनी इसका मूल्यांकन कर रही है. उन्होंने अपने बयान में उन शहरों के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन यह कहा कि वह जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं. गौरतलब है कि एयरबस कंपनी का यह चौथा प्लांट होगा जहां सिंगल-इंजन के हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा. इससे पहले कंपनी के प्लांट अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों में रहे हैं. बता दें कि भारत में सिंगल-इंजन 125 की फाइनल असेंबली लाइन प्राइवेट सेक्टर में नागरिक हेलीकॉप्टर बनाने वाली पहली कंपनी है. एयरबस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की भारी मांग होगी. इसके बाद कंपनी को उम्मीद है कि इस प्लांट से हर साल 10 हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा जिसका शुरुआत साल 2026 से शुरू हो जाएगा. Olivier Michalon ने यह भी कहा कि भारत में निर्मित होने वाले हेलीकॉप्टर न सिर्फ कम समय में बनेंगे बल्कि यह आसपास के पड़ोसी देशों की डिमांड को भी पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि एच 125 हेलीकॉप्टर भारत में ए320 एयरबस के समान ही सफल होंगे. भारत के गुजरात के वडोदरा में एयरबस की पहली असेंबली साइन लगभग बनकर तैयार हो चुकी है. इसमें एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा.

रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ का मुनाफा, किसानों के एक रुपये का ऋण माफ नहीं, 22 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली ।

एनडीए सरकार का पहला बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने किसान दांव चल दिया है। सांसद और पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमताहीनता व दुर्भावना से भरा व्यवहार सबसे अधिक हानिकारक है। यूपीए सरकार ने गेहूं की एमएसपी 119 फीसदी और धान की एमएसपी में 134 फीसदी बढ़ाई थी, वहीं मोदी सरकार ने इसे क्रमशः 47 फीसदी और 50 फीसदी बढ़ाया है। यह महंगाई और कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतों के हिसाब से बिलकुल भी लिए पर्याप्त नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ष्ट2+50त्र फॉर्मूले के तहत, एमएसपी के अंतर्गत आने वाली 22 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया जाए। इस साल आरबीआई से रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ का लाभांश मिलने के बावजूद, किसानों के एक रुपये का कृषि ऋण भी माफ नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने कहा, गेहूं और धान की एमएसपी में मौजूदा वृद्धि, महंगाई और कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतों के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

किसानों का कर्ज बहुत बढ़ गया है। एनएसएसओ के अनुसार, 2013 के बाद से बकाया ऋण में 58 फीसदी की वृद्धि हुई है। आधे से यादा किसान कर्ज में डूबे हैं। 2014 के बाद से हमने 1 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या से मरते देखा है। कांग्रेस नेता ने आगामी बजट में कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तीन मुख्य घोषणा किए जाने की आवश्यकता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सी2+50फीसदी के फॉर्मूले के अनुरूप, 22 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाएं। सरकार की अपनी मान्यता कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देकर लागू करने के लिए सभी कृषि उत्पादों की खरीद की आवश्यकता नहीं है, के विपरीत एमएसपी को कानूनी दर्जा दें। इसे मजबूती से लागू करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें, जिसमें रणनीतिक खरीद, बेहतर विनियमन और मूल्य अंतर मुआवजा शामिल है। इसके लिए बस नियत और साहस की आवश्यकता है।किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने, और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जाए। इस अत्यंत आवश्यक कदम से कर्ज में डूबे किसानों को राहत मिलेगी। याद रखें कि केंद्र सरकार के पास इन तीनों कदमों को उठाने के लिए पूरी शक्ति है। सिर्फ इस बात का इंतजार है कि स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री थोड़ी हिम्मत दिखाएं और अपनी जिद को छोड़कर किसानों के हित में फैसला लें। नवंबर 2021 में, तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने एमएसपी से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। सरकार को समिति गठित करने में आठ महीने लगे। दो साल बाद भी, उसने अभी तक कोई अंतरिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अगर सरकार चाहती तो अब तक रिपोर्ट जारी हो जाती। इससे एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल जाता। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राय में कर्ज लिए हुए किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करना शुरू कर दिया है। इससे कुल 40 लाख किसानों को 2 लाख रुपये तक के लोन पर राहत मिलेगी। 2008 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए ने 72,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया था। इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ हुआ था। लाभार्थियों में यूपी के 54 लाख किसान, महाराष्ट्र के 42 लाख किसान, हरियाणा के 8.9 लाख किसान, बिहार के 17.6 लाख किसान और झारखंड के 6.66 लाख किसान शामिल थे। नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार ने पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण माफ किए हैं। दूसरी तरफ, इस साल आरबीआई से रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ का लाभांश मिलने के बावजूद इसने किसानों के एक रुपए का कृषि ऋण भी माफ नहीं किया है। 4 जून को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार के घावों से अभी भी उबर रहे स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री क्या कृषि कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठायेंगे?

आर्थिक सर्वे ने कहा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत नहीं ले सकता है चीन का स्थान

नई दिल्ली । दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग करने पर जोर दे रही हैं. भारत इस अवसर का फायदा उठाना चाहता है जिसके लिए भारत सरकार कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लेकर भी आई है. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में साफतौर पर कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के पीछे हटने का फायदा भारत उठा पाएगा ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है. सर्वे के मुताबिक हालिया डेटा इस ओर संदेह भी खड़ा कर रहे हैं कि चीन मैन्युफैक्चरिंग से पीछे हट रहा है. इकोनॉमिक सर्वे में भारत-चीन व्यापरिक रिश्तों पर पूरा अध्याय लिखा गया है. सर्वे के मुताबिक भारत-चीन के बीच आर्थिक रिश्ते बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है. कई प्रोडेक्ट्स के ग्लोबल सप्लाई-चेन में चीन का वर्चस्व वैश्विक चिंता का कारण बना हुआ है. खासतौर से यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान सप्लाई में दिक्कतों ने ये चिंता और भी बढ़ा दी है. जी-20 देशों में भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था है और चीन के मुकाबले भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यादा है. इसके बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वे में सरकार को सुझाव दिया है कि, भारत को अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए खुद को चीन के सप्लाई-चेन में शामिल कर लेना चाहिए या फिर चीन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना चाहिए. क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनिरल्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में चीन की मोनोपॉली से दुनियाभर की चिंताएं बढ़ी हुई है. इससे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के कचे माल के लिए भारत आयातित कचे माल पर निर्भर है.

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ऐसे में ये सोचना कतई मुनासिब नहीं होगा कि चीन के कुछ मामलों में मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हटने का भार भारत उठा सकता है. सर्वे के मुताबिक हालिया डेटा से ये साफ है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग से कतई पीछे नहीं हट रहा है. ऐसे में भारत के सामने कई सवाल हैं.

पहला – क्या चीन की सप्लाई-चेन में दखल दिए बगैर क्या भारत ग्लोबल सप्लाई-चेन में अपनी दखल बढ़ा सकता है?

दूसरा – चीन से गुड्स के इंपोर्ट करने और पूंजी इंपोर्ट करने के बीच सही बैलेंस भारत के लिए क्या है?

दस साल में जीडीपी के 55 फीसदी से यादा हुआ आंतरिक कर्ज, सरकार ने बताया कौन रहा जिम्मेदार

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बीते 10 सालों के कार्यकाल में बाहरी कर्ज का दबाव भले ही कम हुआ हो, लेकिन आंतरिक कर्ज का बोझ बढ़ गया है. पिछले 10 साल के दौरान देश का आंतरिक कर्ज इतना बढ़ा है कि आंकड़ा अब जीडीपी के 55 फीसदी के भी पार निकल गया है.केंद्रीय वित्त राय मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में देश के ऊपर कर्ज के आंकड़ों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश के ऊपर आंतरिक कर्ज के आंकड़े में बीते 10 साल के दौरान तेजी आई है और अब यह जीडीपी के 55 फीसदी से यादा हो गया है. आंकड़ों के अनुसार, देश के ऊपर 2013-14 में जीडीपी के 48.8 फीसदी के बराबर आंतरिक कर्ज था. अब यह आंकड़ा बढ़कर 2023-24 में जीडीपी के 55.5

फीसदी के बराबर पर पहुंच गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने देश के ऊपर कर्ज की स्थिति के बारे में लोकसभा में सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा था कि बीते 10 सालों में भारत का आंतरिक और बाहरी कर्ज कितना बढ़ा है. उन्होंने उसके साथ ही सरकार से ये भी जानना चाहा था कि सरकार ने कर्ज में लिए गए पैसों को कहां खर्च किया है. वित्त राय मंत्री ने जवाब में आगे बताया कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के आंतरिक कर्ज में जो तेजी आई है, उसके लिए मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी जिम्मेदार है. सरकार के अनुसार, कोविड-19 महामारी के चलते आंतरिक कर्ज 2020-21 में बढ़कर जीडीपी के 58.3 फीसदी के बराबर पर पहुंच गया था, जो महामारी शुरू होने से पहले 2018-19 में जीडीपी के 46.4 फीसदी के बराबर था. सरकार का कहना है कि फिस्कल कॉन्सोलिडेशन पर जोर देने से कर्ज के मोर्चे पर तेजी से सुधार आया है. 2020-21 में जो आंकड़ा जीडीपी के 58.3 फीसदी के बराबर पर पहुंच गया था, वह कम होकर बीते वित्त वर्ष में जीडीपी के 55.5 फीसदी के बराबर रह गया. सरकार ने कहा कि उसने कोविड के बाद के सालों में कर्ज को तेजी से कम किया है. खर्च के बारे में सरकार ने कहा कि कर्ज से जुटाए गए संसाधनों का मुख्य रूप से विकास, समाज कल्याण आदि मदों में इस्तेमाल किया गया.

आम यात्रियों को बजट में मिल सकती हैं इन खास ट्रेनों की सौगात, इन रायों के 75 शहरों से होगी शुरू

नई दिल्ली । मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। इस बजट में ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों को भी कई बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तमंत्री इस बजट में आधुनिक और तेज गति वाली 200 से अधिक नई नॉन एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सकती है। इन ट्रेनों के जरिए पहली बार देश के 75 छोटे शहरों (तीन लाख आबादी वाले) को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। पुल-पुश तकनीय से युक्त इन अमृत भारत ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच होंगे। कुछ रेलमार्गों पर डिमांड के अनुसार इन ट्रेनों में एसी कोच लगाए जा सकते हैं। ये अमृत भारत ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्यप्रदेश आदि रायों के छोटे शहरों से रोजगार की तलाश में देश के महानगरों में जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर चलाई जाएंगी। इनका किराया सामान्य मेल-एक्सप्रेस की तरह ही होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 में हाई स्पीड और सेमी हाईस्पीड ट्रेनों को भी प्राथमिकता मिलेगी। वित्त मंत्री देश के उत्तर, पूर्व व दक्षिण भारत के हिस्से में तीन नए हाई स्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) बनाने की घोषणा कर सकती हैं। इसमें दिल्ली-अमृतसर सहित कोलकाता और चेन्नई को शामिल किया जा सकता है। कॉरिडोर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बजट में वंदे भारत व वंदे मेट्रो को संख्या बढ़ाने का एलान भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार, बजट में बढ़ते रेल हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नए रेलमार्गों पर टक्कर रोधी तकनीक वर्जन कवच-4.0 की घोषणा की जा सकती है। इसके तहत 35,736 किलोमीटर रेलमार्गों पर कवच लगाया जाएगा। कचव तकनीक ट्रेनों की आमने-सामने व पीछे से टक्कर रोकने में सक्षम है। ड्राइवर के चूक करने पर कवच ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। नए रेल मार्ग में दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-कोलकाता एवं स्वर्मिण विकर्ण (गोल्डन डायगनल) के दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा वित्तमंत्री भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए रेलवे का बजट बढ़ा सकती है। वित्तमंत्री रेलवे को 2.85 से तीन लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन कर सकती है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 10-15 फीसदी अधिक होगा।

हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत व नियमित मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच बढ़ाने के लिए 12,500 कोच उत्पादन की मंजूरी दी है।

शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास डीटीसी बस पिलर से टकराई, एक की मौत और 23 घायल

पश्चिमी दिल्ली। सावन के पहले सोमवार के दिन मंगोलपुरी से आनंद विहार जा रही 939 नंबर रूट की दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की इलेक्ट्रिक क्लस्टर बस शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर व डिवाइडर पर लगे पेड़ों को तोड़ते हुए मेट्रो के पिलर से जा टकराई। दुर्घटना में बस चालक, कंडक्टर समेत 24 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। एक पुरुष यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। मृतक महिला की पहचान सुल्तानपुरी की सविता और गंभीर रूप से घायल यात्री की पहचान निहाल विहार के शरीफ के रूप में हुई है। पंजाबी बाग थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों, बस के कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ घायल यात्रियों से भी इस बार में पूछताछ कर रही है। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि सोमवार सुबह सात बजकर 42 मिनट पर पंजाबी बाग थाना पुलिस को जानकारी मिली कि रोहतक रोड पर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बस दर्घटनाग्रस्त हो गई है। पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि 939 रूट नंबर की डीटीसी इलेक्ट्रिक बस मंगोलपुरी से आनंद विहार जा रही थी। वह अचानक से मेट्रो पिलर नंबर 146 से टकरा गई है। अचानक ब्रेक लगने के कारण एक ऑटो रिक्शा पीछे से बस से टकरा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना में डीटीसी बस चालक व कंडक्टर समेत 24 लोग घायल हो गए। 14 यात्रियों को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भेजा गया और दस यात्रियों को मोती नगर के आचार्य भिक्षु अस्पताल में ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर ने 45 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय यात्री अग्रसेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सहायता और निकासी के लिए पीसीआर वैन और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन कम समय में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटना के निरीक्षण के लिए क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। उनकी रिपोर्ट और वाहन के निरीक्षण के आधार पर दुर्घटना के कारण का पता लग पाएगा। पंजाबी बाग थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच कर रही है।

नेमप्लेट विवाद पर उचतम न्यायालय ने लगाई अंतरिम रोक, आप ने किया स्वागत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कावंड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले भोजनालय, रेस्तरां एवं खानपान की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के कथित 'दलित विरोधी आदेश पर उचतम न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का सोमवार को स्वागत करते हुए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दलित विरोधी है। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा का एक लक्ष्य आरक्षण को समाप्त करना था। वे क्यों 400 पार का नारा लगा रहे थे? पूरे देश के दलितों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। इसका बदला लेने के लिए भाजपा सरकारों ने ऐसे आदेश दिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी कर कावंड यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले रेस्तरां, खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा मध्यप्रदेश के उजैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने नाम और मोबाइल फोन नंबर अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। आतिशी ने कहा, ''हिंदुओं में पुरानी मान्यता थी कि दलितों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज के समय में इस तरह की मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। सभी राजनीतिक दलों को ऐसी मान्यताओं को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, '' जब भाजपा सरकारों ने जाति और उपनाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया तो इसका अभिप्राय है कि कावंड़ यात्री दलितों द्वारा संचालित भोजनालयों का खाना नहीं खाएं। मैं उचतम न्यायालय को इस दलित विरोधी आदेश पर रोक लगाने के लिए धन्यवाद देती हूं। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। इस बीच, आतिशी ने सोमवार ने कहा कि कावंड़ यात्रियो का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 185 शिविर स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रास्ते 15 से 20 लाख कावंड़ यात्री गुजरने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कावंड़ियों का आना 25 जुलाई से शुरू होगा और आने वाले दिनों में इन शिविरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में उनके रहने खाने और चिकित्सा की सुविधा होगी।

मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत की अवधि

नई दिल्ली । दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की यूडिशियल कस्टडी को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है. सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो रही थी. इससे पहले कोर्ट ने 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए सिसोदिया को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आप के पूर्व मंत्री को आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार गिया गया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया. कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए 29 जुलाई तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा, नोटिस का जवाब 29 जुलाई तक दें. हम दो सप्ताह बाद इस पर फिर विचार करेंगे. मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि वरिष्ठ आप नेता 16 महीने से जेल में हैं और केस आगे नहीं बढ़ रहा है. पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीने में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार रेगुलर बेल मांग रहे थे. जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि मामले की कार्यवाही में देरी काफी हद तक सिसोदिया के कारण ही हुई है. इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक दोहरी शर्तों को वो पूरा नहीं करते.

इसे चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. पिछले महीने, शीर्ष अदालत में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा था कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोप पत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी .बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था.

दिल्ली में सैकड़ों पेड़ काटने पर आप का एलजी के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली ।

दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध रूप से 1100 पेड़ों को काटे जाने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. आप के कार्यकर्ताओं ने ह्यूमन चेन बनाकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी मुख्यालय पर ''आप'' के कार्यकर्ता अपने हाथों में नारे लिखे पोस्टर-बैनर के साथ पेड़ का स्ट्रक्चर और आरी लिए थे. आप (कार्यकर्ताओं ने उपरायपाल का मुखौटा पहनकर नारेबाजी करते हुए पेड़ के प्रतीकात्मक स्ट्रक्चर को आरी से काट कर एलजी के खिलाफ अपना विरोध जताया. आप के विधायक राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता और आदिल समेत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तीन फरवरी 2024 को मुख्य सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ उपराज्यपाल विनय सक्सेना रिज का दौरा करने गए थे. उसी दौरान उन्होंने 1100 पेड़ काटने के मौखिक आदेश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार पूछा कि किसके आदेश पर इतने पेड़ काटे गए, लेकिन अफसरों ने सच नहीं बताया. सड़क को चौड़ा करने के लिए फार्म हाउसों की जमीन ली जा सकती थी, लेकिन यहां फार्म हाउस मालिकों को फायदा पहुंचाना था, इसलिए रिज क्षेत्र के सैकड़ों पेड़ काट दिए गए. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़क को चौड़ा करने के लिए अगर वो हर फार्म हाउस से करीब पांच से 10 फीसद ही जमीन ले लेते तो पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए सड़क चौड़ी की जा सकती थी. ऐसा न कर फार्म हाउसों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रिज के पेड़ों को काटा गया. इससे साफ पता चलता है कि पेड़ों को काटने में भारी गड़बड़ी की गई है.

विपक्ष ने खुब उठाया संसद में नेम प्लेट वाला मुद्दा

नई दिल्ली। कावड़ यात्रा दौरान नेम प्लेट लगाने का मुद्दा आजकल बहुत जोर शोर से उठ रहा है। क्या आप जानते है इसके पीछे का पुरा मामला योगी सरकार ने ऐसा कौन सा फरमान सुना दिया था जिसने सभी का ध्यान अपनी औऱ आकर्षित किया। सीएम योगी के इस फरमान की निंदा विपक्ष ने संसद सत्र के पहले दिन ही शुरू कर दी थी। संसद के मानसून सत्र की शुरूआत के साथ ही दोनों सदनों में ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरना तो अब तय लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। योगी सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि कावड़ यात्रा दौरान उन रास्तों पर जहां से ये यात्रा गुजरेगी में पड़ने वाले सभी दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरुरी होगा जिससे यात्रियो को ये पता रहे कौन सी दुकान किसकी है जिससे तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहे। इसी विवाद को लेकर विपक्ष नें सरकार पर हमला बोल दिया। वहीं सरकार को झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर रोक लगा दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने योगी सरकार पर भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। संसद में कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने इस फैसले को विभाजनकारी बताया और कहा इससे समाज में तनाव पैदा होगा। यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। गांधी ने आरोप लगाया कि इस 'विभाजनकारी एजेंडे' को लागू करके भाजपा अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहती है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर रायसभा में चर्चा की मांग की थी और विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में दिए गए निर्देश को लेकर आज का नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा की मांग की गई थी। धनखड़ ने कहा कि ये नोटिस न तो नियम 267 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और न ही आसन की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुरूप हैं। इसलिए इन्हें अस्वीकार स्वीकार किया जाता है। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा दौरान अपनी इछा से दुकान मालिकों को दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का आग्रह किया था। औऱ उन्होंने ये भी कहा ये हमारा मकसद धार्मिक भेदभाव पैदा करना नही है बल्कि केवल भक्तों की सुविधा के लिए है। उन्होंने ये भी कहा पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जब कांवड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई है।

बहुत गलतियां हैं : सोमनाथ भारती की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा- पहले इसमें सुधार करो, फिर करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ एक याचिका दायर की है. सोमनाथ भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनौती दी है. इस पर आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को मामले सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोमनाथ भारती की याचिका में कई गलतियां देखीं. इस पर उन्होंने सोमनाथ भारती की फटकार भी लगाई और सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी. सोमनाथ भारती की याचिका में हाईकोर्ट ने कई टाइपो पाए. हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में खाली टाइपोज हैं सोमनाथ भारती से जस्टिस अरोड़ा ने कहा, 'आपकी याचिका टाइपिंग की गलतियों से भरी है, मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है.' जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में रेफर किये गए प्रतिवादियों का जिक्र पक्षकारों की सूची से मेल नहीं खाता. जज ने विशेष रूप से इशारा किया कि याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 का उल्लेख है, जबकि पक्षकारों की सूची में ऐसा कोई नाम नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'यह (याचिका) गलतियों (टाइपोज) से भरी है. बहुत सी त्रुटियां हैं आपको पहले याचिका को ठीक करना होगा. मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा हैज मैं सुनवाई स्थगित करती हूं और आप सुधार के साथ याचिका दायर करें.' मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी. बता दें कि याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले. दोनों नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और स्वराज को विजेता घोषित किया गया था. याचिका में कहा गया, 'मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (भारती) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (स्वराज) के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई, 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 'भ्रष्ट आचरण' किया है.' याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए भाजपा द्वारा खड़ा किया गया था.

आमदनी दोगुनी तो हुई नहीं, किसानों की लागत बढ़ा दी; नॉनस्टॉप नहीं फुलस्टॉप बन गया हरियाणा, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा हमला

चंडीगढ़।

हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाल हमने पूछे हैं। हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया।

हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 36 बिरादरी ने हुड्डा को लाने का मन बनाया है। महंगाई और बेरोजगारी में प्रदेश नंबर वन हो गया है। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। सरकार ने किसानों की लागत बढ़ा दी। हरियाणा नॉन स्टॉप नहीं फुल स्टॉप बन गया है। अस्पताल में डॉक्टर, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी। बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा पिछड़ गया। आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर बैन हटाने को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को नॉन पॉलिटिकल ही होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को न्यूट्रल रहना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों पर लगातार ईडी के एक्शन पर उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए मैं इस बारे में यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है इसका माकूल जवाब हरियाणा की जनता अपने आप दे देगी। नूह मामले को लेकर हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए पहले पिछली बार जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए।

अजय चौटाला को चौधरी बृजेंद्र सिंह ने दी नसीहत, कहा- राजनीति में ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए

चरखी दादरी । पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह हलके मे अपने जनसंपर्क अभियान के तहत खरकभूरा, दुर्जनपुर, उदयपुर, नचार खेड़ा गांव पहुंचे। यहां पर उनका लोगों ने स्वागत किया। यहां पर भाजपा, आप सहित जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब के बाद हरियाणा में भी किसान संगठनों द्वारा पार्टी बना कर चुनाव लड़ने के फैसले लेने एवं गुरनाम चढ़ूनी के पार्टी बनाने के सवाल पर बोलते हुए पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब में जो इन्होंने चुनाव लड़ा उससे सबक ले लेना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन एक अलग चीज है और चुनाव एक बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। जब पंजाब में चुनाव लड़े तो 17, 18 सीटों पर लड़े तो क्या हश्र हुआ था, वहां पर थोड़ा और कुछ नहीं जो आदमी की

केबरेलिटी है ना उस पर सवालिया निशान लग जाता है। आम आदमी पार्टी द्वारा पांच गारंटी के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ने पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि ये वो चीजें है, जो कोई भी पार्टी है। सरकार में आने पर सबसे पहला प्रयास ये ही होता है कि शिक्षा अच्छी प्रदान की जा सकें, इंफ्रास्टक्चर अच्छा दिया जा सके। मेडिकल सुविधा अच्छी दी जा सकें, बिजली सुविधा अच्छी दी जा सकें। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मैं कोई सीरियस प्लेयर नहीं मानता। हरियाणा में कम से कम 2024 का चुनाव है। उसमें मुकाबला सीधा-सीधा कांग्रेस, बीजेपी के है। तीसरे, चौथे गठबंधन की हरियाणा में कोई जगह नहीं है। भाजपा द्वारा नॉन स्टॉप हरियाणा के माध्यम से किए जा रहे प्रचार पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये एक जुमला है। नॉन स्टॉप लोगों की तकलीफ बढ़ाना। नॉन स्टॉप कभी वो पोर्टल कभी ये कभी वो परेशान कर रखे है लोग। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति नॉन स्टॉप बिगडने लग रही है। उसके ऊपर कुछ कर ले तो बेहतर होगा बजाए जुमलेबाजी के। अजय सिंह चौटाला द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि ऐसी हलकी बात किसी नेता को नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात कभी किसी नेता को दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए। ये ओछी चीजें है, लोगों में अछा संदेश नहीं जाता। इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए।

नारायणगढ़ हत्याकांड : पकड़ा गया भाई के परिवार का हत्यारा,एसपी ने बताई हत्या की हैरान कर देने वाली वजह

अंबाला ।

हरियाणा में अंबाला में रिटायर्ड फौजी ने अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नारायणगढ़ इलाके में उसने मां-भाई समेत 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मरने वालों में भाई की 5 साल का बेटी और 6 महीने का बेटा भी शामिल है। वहीं घायल 6 वर्षीय परी बालिका ने चंडीगढ़ में भी दम तोड़ दिया। वहीं अंबाला के एसपी सुरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है।

आरोपी भूषण ने ससुराल वालों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ये मामला जमीन के रास्ते के विवाद का है। आरोपी भूषण ने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। हमने मृतक के पिता के बयानों पर भूषण समेत कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इन्होंने तेजधार हथियारों से हत्या के बाद शवों को जलाने का प्रयास भी किया है। यह घटना नारायणगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले गांव पीर माजरी के पास डेरे की है। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद रात को ही शवों को जलाने का प्रयास किया। वहीं अंबाला एसपी सुरेंद्र कुमार ने रात 3 बजे घटनास्थल का दौरा किया। अधजले शवों को अम्बाला कैंट अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों में आरोपी की मां, उसका भाई, भाई की पत्नी और इनके 2 बचे शामिल हैं। इनकी पहचान हरीश कुमार (35), उसकी पत्नी सोनिया (32), मां सरोपी देवी (65), हरीश की बेटी यशिका (5), 6 माह का बेटा भूपेश व 6 वर्षीय परी बालिका के रूप में हुई है। आरोपी ने इन सभी को तेजधार हथियार से रात में काट डाला। इस बीच आरोपी के पिता ओम प्रकाश ने वारदात का विरोध किया तो आरोपी ने पिता को भी पीट कर घायल कर दिया। घायल पिता नारायणगढ़ के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। अब पुलिस इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है।

हरियाणा बाल विकास परिषद के पूर्व मानद सचिव प्रवीण अत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ

चंडीगढ़ ।

हरियाणा बाल विकास परिषद के पूर्व मानद सचिव प्रवीण अत्री ने आज भाजपा पार्टी का साथ छोड कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अत्री को पार्टी में वॉइन करवाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के साढ़े नौ साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी खुलकर काम करने का मौका नहीं दिया गया। वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वालों को उचित मान सम्मान मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। वहीं राव दानसिंह और अन्य विधायकों पर ईडी की जांच को लेकर हुड्डा बोले कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता जवाब देगी। वहीं बजट को लेकर कहा जैसे 10 साल में हुआ वैसे ही महंगाई बढ़ेगी। बीजेपी

का हरियाणा नॉन स्टॉप नहीं इन्होंने फुलस्टॉप हरियाणा बना दिया है। हुड्डा ने कहा कि किसानों की आमदनी नहीं बल्कि लागत को दोगुना कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने आप से साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो वहीं आप पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि आप पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। 2014 तक रोजगार, नौकरी, खेल आदि क्षेत्रों में नंबर वन रहा है। उन्होंने कहा कि दुबारा कांग्रेस सरकार हरियाणा को नंबर वन बनाएगी। कांग्रेस ने रेलवे लाइन, थर्मल पावर प्लांट, यूनिवर्सिटी आदि बनाया लेकिन बीजेपी एक का भी नाम बता दे जो बनाया हो। हमारी सरकार में शॉर्ट टर्म लोन किसानों के लिए ब्याज 4 प्रतिशत किया है, और किसान का कर्ज माफ किया है।

हुड्डा को ये नहीं पता कि टिकट मिलेगी या नहीं... अजय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज

सिरसा । हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वहीं विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले करती नजर आ रही है। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा की वो तो 70 सीटों को जीतने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री बनने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी खुद की टिकट का भरोसा नहीं मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। उन्हें तो सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी पकड़ने पड़ेगी, कहीं वेणुगोपाल की चप्पल उठाने पड़ेगी, तब जाकर कोई बात बनेगी। जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाते हुए डबवाली शहर में शहरी व ग्रामीण स्तर का

चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। जिसमे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए विधिवत रूप से हवन यज्ञ किया। चौटाला रोड पर खोले गए इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अजय सिंह चौटाला ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी विशेष रूप से मौजूद रहें। इस मौके पर उपस्थित भारी जनसमूह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला से दिग्विजय सिंह चौटाला को डबवाली विधानसभा से जेजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। इस अवसर पर डा. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही सरकारों का गठन होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों को क्या क्या जतन करने पड़े, लेकिन जेजेपी की टिकट किसको देनी है, इसका फैसला कार्यकर्ताओं से पूछ कर करेंगे और जिसे आप कहोगे उसे ही उम्मीदवार बनाया जायेगा। उन्होंने ने कहा की हम तो इंटरनेशनल मांगते है जो हमने रोजाना मांगने का काम करना है। एक बार वोट नहीं देंगे तो दूसरी बार आ जाएंगे, फिर भी नहीं दोगे तो तीसरी बार आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं दिए तो चौथी बार चिमटा लेकर आ जाएंगे कि अबकी बार तो वोट दो।

शराब न मंगाने पर उतारा मौत के घाट, गन्ने के खेत में पड़ी मिली किसान की लाश; वारदात से पहले बेटे को किया था फोन

पलवल। हसनपुर थाना अंतर्गत गांव सहदेव का नंगला में शराब नहीं मंगाने पर किसान की हत्या कर दी गई। किसान का शव खेत में गन्ने की फसल के बीच पड़ा हुआ मिला। हसनपुर थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पुत्र की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हसनपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार के अनुसार, मामले में गांव चांदहट के रहने वाले नरेंद्र ने शिकायत दी है कि उसके पिता धर्मवीर ने गांव सहदेव का नंगला में खेत पट्टे पर लिए थे। बीती 19 जुलाई को शाम के करीब सात बजे उसके पिता का फोन आया। उसके पिता धर्मवीर ने कहा कि उसे पेप्सी, गुलशन, टिंकू और दो अन्य ने जबरदस्ती शराब पिला दी है। उक्त लोग उससे शराब मंगाने की मांग कर रहे हैं। बताया कि शराब नहीं मंगाने पर उक्त लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद उनके पिता ने फोन काट दिया। उन्होंने अगले दिन अपने पिता को फोन मिलाया, मगर फोन बंद आ रहा था। इसके बाद वह अपने स्वजन को लेकर सहदेव का नंगला पहुंचा और अपने पिता की तलाश शुरू कर दी। उन्हें गन्ने के खेत में उनके पिता का शव मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। हसनपुर थाना प्रभारी के अनुसार, इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं। जिला नागरिक अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

किसान संगठनों का हरियाणा सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम, मांगें न मानीं तो बनाएंगे अगली रणनीति

चंडीगढ़ । किसान आंदोलन और दिल्ली कूच की सुगबुगाहट के बीच हरियाणा सरकार और हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। कई अन्य मांगों में सुधार को लेकर आश्वासन दिया गया है। अब किसानों ने मांगें पूरी करने के लिए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में मांगें पूरी नहीं होती हैं तो किसान अगली रणनीति बनाएंगे। किसानों की मांगों पर अंतिम फैसला सीएम नायब सैनी लेंगे। मुख्यमंत्री किसानों से बैठक भी कर सकते हैं। एसकेएम ने 14 जुलाई को रोहतक में बैठक की थी और किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था।

रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे विश्व कप तक खेल सकते हैं, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का बयान

नई दिल्ली । विश्व कप 2024 की जीत के बाद से ही यह कहा जा रहा था कि शायद यह विश्व कप विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आखिरी विश्व कप हो, हो सकता है कि दोनों अगले विश्व कप तक सन्यास की घोषणा कर दे लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उनके फैंस के लिए एक अछी उम्मीद दी है। नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सोमवार, 22 जुलाई को विराट कोहली और रोहित शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए शानदार काम जारी रखने का समर्थन करते हुए कहा कि ये दोनों दिग्गज आगे चलकर वनडे और टेस्ट का अहम हिस्सा होंगे। गंभीर ने कहा कि रोहित और कोहली चैंपियंस ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के लिए अपना सब कुछ देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उन्होंने 2025 सीज़न के बाद भी जारी रखने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने कहा कि ÷मुझे लगता है कि उन्होंने दिखाया है कि वे बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं, चाहे वह टी20 विश्व कप हो या 50 ओवर का विश्व कप। उन दोनों लोगों में बहुत क्रिकेट बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। गंभीर ने भारत के श्रीलंका दौरे से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होने वाली है। वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रेरित होंगे और अगर वे अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं, तो 2027 विश्व कप खेल सकते हैं। गंभीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोहली और रोहित यहां से वनडे और टेस्ट में भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण मैच खेलेंगे, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि टी20ई प्रारूप से सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने कार्यभार को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमरा जैसे खिलाड़ी के लिए कार्यभार प्रबंधन महत्वपूर्ण है। रोहित और विराट टी20 नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें अधिकांश महत्वपूर्ण खेलों के लिए उपलब्ध रहना होगा। एक बल्लेबाज के लिए, अगर वह अछा क्रिकेट खेल सकता है और अछी फॉर्म में हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। सभी मैच अछे से खेलें, न केवल जसप्रीत बुमराह के लिए, बल्कि अधिकांश गेंदबाजों के लिए कार्यभार प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

हार्दिक पंड्या की जगह सूर्यकुमार को क्यों बनाया टी20 टीम का कप्तान? चीफ सेलेक्टर अगरकर ने गिना दी सारी वजह

मुंबई । हार्दिक पंड्या की जगह आखिर सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम का कप्तान क्यों बनाया गया? श्रीलंका दौरे के लिए टीम के ऐलान के बाद से ही सभी क्रिकेटरप्रेमियों के मन में यह सवाल उठ रहा है. अब बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सोमवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजह बताई है. उन्होंने बताया कि फिटनेस, ड्रेसिंग रूम से मिले फीडबैक और लगातार उपलब्धता के फैक्टर को ध्यान में रखकर सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया. अजीत अगरकर सोमवार को टीम के नए चीफ कोच गौतम गंभीर के साथ श्रीलंका दौरे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरे पर भारतीय टीम मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन टी20 और इतने ही वनडे मैच खेलेगी. इस वाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगरकर ने कहा, 'फिटनेस एक बड़ी चुनौती थी और हम ऐसा कोई खिलाफ चाहते थे जो अक्सर उपलब्ध रहे.' उन्होंने कहा, 'वह सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं और कप्तान के रूप में, उनके सभी मैच खेलने की उम्मीद है. हमें लगता है कि वह एक काबिल कप्तान हैं और हम देखेंगे कि वह इस भूमिका में कैसे फिट होते हैं.' वहीं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के बारे में अगरकर ने कहा, 'हार्दिक जैसा स्किल सेट और फिटनेस मिलना मुश्किल है. हमें थोड़ा और समय मिला है और हम कुछ चीजों पर गौर कर सकते हैं.' अगरकर ने कहा, 'फिटनेस एक बड़ी चुनौती थी और हम ऐसा कोई व्यक्ति चाहते थे जो अक्सर उपलब्ध रहे.' उन्होंने आगे कहा, हमने ड्रेसिंग रूम से भी आम राय ली है.' वहीं पूर्व उप-कप्तान केएल राहुल की अनदेखी के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने जवाब दिया, 'जब केएल को हटाया गया था तो मैं वहां नहीं था.'

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी, इसके बाद 28 और 30 जुलाई को मैच खेले जाएंगे. ये सभी मैच पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. सूर्यकुमार यादव तीन मैचों में 15 सदस्यीय टी20 टीम का नेतृत्व करेंगे. इसके बाद वनडे 2, 4 और 7 अगस्त को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे. पिछले महीने वेस्टइंडीज में भारत को विश्व कप दिलाने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान के रूप में वापसी करेंगे.

रविंद्र जडेजा को वनडे सीरीज के लिए टीम में क्यों नहीं मिली जगह

नई दिल्ली । श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिला है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के चैंपियन बनने के बाद जडेजा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका चयन न होने पर सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं उनका वनडे करियर भी तो समाप्त होने की कगार पर तो नहीं है। भारत के श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अजीत अगरकर ने जडेजा को लेकर कहा कि आगे खूब टेस्ट क्रिकेट होना है, ऐसे में उन्हें वनडे सीरीज में नहीं चुना गया। अगरकर ने ये भी कहा कि टीम घोषित करते वक्त ही साफ कर देना चाहिए था कि वह ड्रॉप नहीं हुए हैं, बल्कि आराम दिया गया है। साथ ही अगरकर ने कहा कि, अक्षर और जड्डू दोनों को 3 मैचों की सीरीज के लिए लेना व्यर्थ होता। उन्होंने (जडेजा) वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं किया गया। अगर हम उन्हें लेते तो उनमें से कोई भी हर मैच नहीं खेल पाता। एक बड़ा टेस्ट सीजन आने वाला है। मुझे लगता है कि शायद हमें टीम की घोषणा करते समय ही ये स्पष्ट कर देना चाहिए था। वह अभी भी फॉर्मेट का हिस्सा हैं वह हमारे लिए बहुत अहम खिलाड़ी भी हैं। रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी वनडे 19 नवंबर 2023 को खेला था। ये मैच वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस मैच में उन्होंने 9 रन बनाए थे जबकि उन्हें किसी भी विकेट की सफलता नहीं मिली थी। वहीं जडेजा के वनडे करियर की बात करें तो 197 मैच की 132 पारी में 32.42 की औसत और 85.06 की स्ट्राइक रेट से 2756 रन बनाए। उन्होंने 13 अर्धशतक जड़े और 87 उनका सर्वोच स्कोर है। 189 पारी में 36.07 की औसत और 4.88 की इकॉनमी से 220 विकेट झटके।

टीम इंडिया में मोहम्मद शमी की वापसी कब होगी? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया जवाब

नई दिल्ली । श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान जब उनसे मोहम्मद शमी की वापसी को लेकर सवाल किया गया तो अजीत अगरकर ने शमी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया। बता दें कि, शमी 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद ही टीम से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने घुटने की सर्जरी भी कराई थी, वह फिलहाल रिकवरी मोड पर है।

अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के कमबैक पर कहा कि, मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू कर दी है जो एक अछा संकेत है। 19 सितंबर को पहला टेस्ट है और हमेशा यही लक्ष्य था। मुझे नहीं पता कि उसकी रिकवरी टाइमलाइन क्या है, इस बारे में एनसीए के लोगों से पूछना होगा। अभी बहुत सारे टेस्ट मैच होने हैं। हमें कुछ गहराई की आवश्यता होगी। बुमराह, शमी, सिराज कुछ समय से खेल रहे हैं, ये स्पष्ट हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ बातचीत होगी। बहुत सारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट आने वाला है इसलिए हम ऐसे खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं। भारत को आने वाले समय में पहला टेस्ट 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। अजीत अगरकर को उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शमी वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर शमी बांग्लादेश के खिलाफ वापसी नहीं कर पाते तो उनके पास अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की टेस्ट सीरीज में वापसी करने का मौका होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी कर शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले खुदको तैयार कर सकते हैं साल के अंत में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

विराट कोहली फैब फोर की रेस में पिछड़े, इंग्लिश दिग्गज निकला आगे, लारा-द्रविड़ का रिकॉर्ड भी खतरे में

नई दिल्ली । विराट कोहली फैब फोर के अपने साथियों से पिछड़ते जा रहे हैं. इंग्लैंड के जो रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को शानदार शतक लगाया. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियम्सन पर बड़ी बढ़त बना ली है. ये चारों क्रिकेटर ही मॉडर्न फैब फोर में शामिल किए जाते हैं. 33 साल के जो रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 120 रन बनाए. जो रूट ने इस पारी की बदौलत सबसे यादा टेस्ट रन के मामले में शिवनारायण चंद्रपाल को पीछे छोड़ दिया. अब उनके निशाने पर ब्रायन लारा हैं.

दिग्गज लारा को पीछे छोड़ने के लिए जो रूट को सिर्फ 14 रन चाहिए. जो रूट के नाम अब 142 टेस्ट मैच में 11940 रन हो चुके हैं. लारा के नाम 131 टेस्ट में 11953 रन दर्ज हैं. ओवरऑल रिकॉर्ड के इतर अगर हम मॉडर्न फैब फोर की बात करें तो जो रूट बाकी तीन बैटर्स से काफी आगे निकल गए हैं. जो रूट फैब फोर में अकेले बैटर हैं, जिन्होंने 10 हजार टेस्ट रन से यादा बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 109 टेस्ट मैच में 9685 रन बनाए हैं. विराट कोहली के नाम 113 टेस्ट में 8848 रन दर्ज हैं. केन विलियम्सन इन चार मॉडर्न ग्रेट्स में चौथे नंबर पर हैं. न्यूजीलैंड के जेंटलमैन बैटर ने 100 टेस्ट मैच में 8743 रन बनाए हैं. स्पष्ट है कि विराट कोहली, स्मिथ और विलियम्सन के मुकाबले जो रूट अब सबसे यादा टेस्ट रन की लिस्ट में काफी आगे निकल गए हैं.

पेरिस में दूसरे देशों के लिए चमक बिखेरेंगे भारतीय मूल के ये खिलाड़ी

पेरिस । पेरिस ओलंपिक को शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। 26 जुलाई को शुरू हो रहे इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 10, 500 से भी यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इसके लिए पेरिस में पूरी तैयारी हो चुकी है। भारतीय एथलीट्स समेत कई अन्य देशों के एथलीट भी पेरिस के खेल गांव पहुंचना शुरू कर चुके हैं। हालांकि, पेरिस ओलंपिक में भारत सिर्फ भारतीय दल तक सीमित नहीं होगा बल्कि भारतीय मूल के कई खिलाड़ी दूसरे देशों के लिए भी अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। इनमें से एक एथलीट तो महज 19 साल की है। हम आपको ऐसे ही कुछ एथलीट्स की जानकारी दे रहे हैं...इस सूची में सबसे जाने माने खिलाड़ी। अमेरिका के डेनवर में जन्मे 40 वर्ष के राजीव के माता पिता बेंगलुरू के रहने वाले थे। राजीव के पिता बोटेनिस्ट थे जिनका 2019 में कैंसर से निधन हो गया। वहीं उनकी मां सुषमा वैज्ञानिक तकनीशियन हैं। राम ने एक बार कहा

था, मुझे अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। टेनिस में बहुत यादा भारतीय नहीं हैं। हम एक समूह के रूप में जो भी कामयाबी अर्जित करेंगे, उससे आने वाली पीढी को प्रेरणा मिलेगी। अमेरिका के लिए खेलते हुए राजीव ने चार पुरुष युगल और एक मिश्रित युगल ग्रैंडस्लैम जीता है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में वीनस विलियम्स के साथ मिश्रित युगल खेला था। इस बार वह पुरुष युगल में भाग लेंगे। प्रिथिका के पिता का जन्म पुडुचेरी में हुआ था। वह 2003 में शादी के बाद पेरिस जा बसे और एक साल बाद यानी 2004 में प्रिथिका का जन्म हुआ। जब वह छह साल की थीं तो खुद टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे उनके पिता ने उन्हें इस खेल से रूबरू कराया। प्रिथिका ने 16 वर्ष की उम्र में तोक्यो में पहला ओलंपिक खेला था। रसायन और पर्यावरण विज्ञान की छात्रा 19 वर्ष की प्रिथिका महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खेलती दिखेंगी। भारतीय मूल के एक और खिलाड़ी कनक झा अमेरिका के लिए खेलेंगे।

गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में हुआ स्मार्टफोन वितरण

बहेड़ी।

गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में डिजिशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र छात्रों को स्मार्टफोन वितरण किये गए। आपको बता दे कि आज बरेली जनपद में सरकार की योजना के अनुसार बहेड़ी तहसील क्षेत्र के एक महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे गए। वही स्मार्टफोन मिलते ही छात्र-छात्राओं के फेर खिल उठे छात्र-छात्राओं ने स्मार्टफोन देने के लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया वहीं प्राचार्य प्रोफेसर डॉ हरिकेश सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि आज जिस प्रकार प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्टफोन देकर छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं डिजिटल रूप से मजबूत किया है इस तरह एक दिन सभी छात्र-छात्राएं प्रदेश एवं देश को मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की विधि शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है।

वहीं नोडल अधिकारी रविंदर गंगवार ने बताया कि कॉलेज के लगभग सभी बचे डिज़ीशक्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि कोई भी छात्र-छात्रा डीजीशक्ति योजना का लाभ उठाने से बंचित न रहे। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरिकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपको ऑनलाइन शिक्षा की प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन दिया है इसका सही इस्तेमाल करें और अपने भविष्य को उजवल करें । वही नोडल अधिकारी रविंद्र गंगवार ने बधाई देते हुए कहा कि आज जिस प्रकार प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्टफोन देकर छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं डीजल रूप से मजबूत किया है इस तरह एक दिन सभी छात्र-छात्राएं प्रदेश में देश को मजबूत करेंगे प्रदेश सरकार की डीजीशक्ति योजना महिला सशक्तिकरण की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरिकेश सिंह नोडल अधिकारी रविंदर गंगवार, सुरेखा पिपलानी, हरनन्दन कुशवाह, सुनील कुमार, संजीब पांडेय, डॉ राजीब यादव,आदि शिक्षक व कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं छात्र-प्रदीप कुमार, दिव्यांशु मिश्रा, आदिल बेग छात्रा तान्या शर्मा आदि को स्मार्टफोन वितरण किये गए।

प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए उपचुनाव का हुआ नामांकन

प्रधान पद के लिए पांच व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए छः ने भरे पर्चे

सुल्तानपुर।

बल्दीराय ब्लाक के अरवल में करीब एक माह से खाली चल रहे प्रधान पद के लिए सोमवार को नामांकन हुआ। इस पद के लिए दावेदारी करते हुए श्यामलाल, मुरलीधर,जय प्रकाश ,सुमेश यादव व राकेश ने पर्चे भरे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 6 अगस्त को चुनाव संपन्न कराया जाएगा।और 8 अगस्त को मतगणना होगी। बल्दीराय ब्लॉक क्षेत्र के अरवल प्रधान बलराम यादव की मौत के कारण पद खाली चल रहा था। ऐसे में 6 अगस्त को प्रधानी के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। इसके कारण आज बल्दीराय ब्लॉक पर प्रधान पद के लिए पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा और उसे भर कर दाखिल किया। तो वही, ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए बिही निदूरा ग्राम पंचायत से समर बहादुर और रेनू सिंह,अरवल ग्राम पंचायत से स्वामी नाथ,असरफपुर ग्राम पंचायत से शांति, कस्बा माफियात ग्राम पंचायत से अशोक कुमार और दौनो ग्राम पंचायत से अनुपम मिश्रा ने नामांकन पत्र खरीदा और उसे भरकर दाखिल किया। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 24 जुलाई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद 6 अगस्त को उपचुनाव कराया जाएगा। बल्दीराय ब्लॉक के निर्वाचन सहायक अधिकारी प्रेमनाथ ने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

7 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती। आदर्श समायोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राम पराग चौधरी के नेतृत्व में जनपद के समस्त बीआरसी केन्द्रों पर शिक्षा मित्रों ने 7 सूत्रीय मागों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि अड़तालीस हजार शिक्षा मित्र 23 वर्षों से निरंतर निष्ठा पूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे है। 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय के उपरान्त शिक्षा मित्रों के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों के चलते लगभग आठ हजार शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। 8 वर्षों से शिक्षा मित्र निरंतर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे है। इनकी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। अध्यादेश के माध्यम से शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक के पद पर स्थापित किये जाने, उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य का 12 माह का समान वेतन व समान सुविधायें दे।

जनपद के सभी बी.आर.सी. केंद्रों पर शिक्षामित्रो ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

सुलतानपुर।

आदर्श शिक्षामित्र एशोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा व महामंत्री उमेश पाण्डेय के आह्वान पर जिले के कुड़वार ब्लाक संसाधन केंद्र पर शिक्षक संघ ,शिक्षामित्र संगठन,व अनुदेशक संगठन ने सयुंक्त रूप से धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिया। तथा अपनी माँगो से सम्बंधित ज्ञापन आज दिनांक 22 जुलाई को 3 बजे खण्ड शिक्षा अधिकारी कुडवार कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा ।यदि हमारी माँगे 15 दिन के अन्दर नही मांगी गयी तो पुनः संगठन आगामी 09 अगस्त को जिला मुख्यालयो पर धरना-प्रदर्शन /आन्दोलन किया जाऐगा । संगठन की प्रमुख मागे- अध्यादेश लाकर स.अ.बनाया जाय ,अध्यादेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य समान वेतन,महिलाओ को उनके ससुराल/ निकटतम विद्यालयो मे स्थानांतरण, मूल विद्यालय/निकटतम विद्यालयो मे समायोजन,मृतक शिक्षामित्रो के परिवार को यथोचित नौकरी व आर्थिक सहायता प्रदान किया जाय। 62 वर्ष की सेवा किया जाय,सहित अन्य मागे भी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नही होती तब तक लगातार आन्दोलन जारी रहेगा। आदर्श शिक्षामित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप यादव मंत्री राजेश त्रिपाठी प्रमोद यादव ,कोषाध्यक्ष मृदुल तिवारी ,प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र त्रिपाठी और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष निजाम खान, मंत्री बृजेश मिश्र ,विनय पांडेय सुहेल सिदीकी ,राजेश मिश्रा कोषाध्यक्ष यूपीएस संघ,सिकंदर वर्मा,मुहम्मद मुतबा,रमन तिवारी,देवशंकर मिश्र शिवबहादुर,जगन्नाथ रामयज्ञ मौर्य, सरिता मिश्रा,मंजू सिंह पूनम वर्मा ,दीपमाला,अनुपम सिंह नीलम अरुण वर्मा ,मनीराम सरदार जितेंद्र मौर्य, श्रवण शुक्ला, मुहम्मद आरिफ,फ़ैज़ उल्लाह अंसारी ,राकेश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे।

बस में घुसकर ड्राइवर, कंडक्टर व हेल्पर को पीटकर किया लहूलुहान

*** युवती से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों ने मचाया उत्पात, रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार**

नवाबगंज, गोण्डा। जनपद अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के श्री किशुनपुरवा निवासी महेश कुमार वर्मा ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि वह डबल डेकर बस का ड्राइवर है जो बभनान से दिल्ली तक आती-जाती है। रविवार को वह बभनान से बस में सवारी बैठा कर दिल्ली जा रहा था कि अयोध्या-गोंडा राजमार्ग पर कस्बे के पड़ाव मोहल्ले में एसएमआई इंटर कालेज के सामने करीब 03 बजे कस्बे के चांईटोला मोहल्ला निवासी अल्ताफ शेख ने एक दर्जन अन्य लड़कों के साथ बस को जबरन रोक लिया। आरोप लगाया है कि वह और उसके साथी बस में चढ़कर डंडा व लोहे के राड से उसे मारने लगे। बीच बचाव करने आए बस के कंडक्टर विजय पांडेय अगयामापी थाना छपिया व हेल्पर आनंद निषाद निवासी अल्लीपुर बाजार थाना खोड़ारे को भी राड व डंडों से मारा पीटा, जिससे तीनों लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं। मार-पीट के दौरान रूपयों से भरा बैग गिर गया जिसमें 92500 रूपया रखा था। काफी खोजबीन के बाद भी बैग नहीं मिल पाया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

छेड़छाड़ का विरोध पड़ा महंगा

बस चालक महेश वर्मा ने बताया कि वह बीते शुक्रवार को दिल्ली से बस को लेकर आ रहा था जिसमें अल्ताफ शेख भी सवार था। रास्ते में मनचले अल्ताफ ने बस में बैठी एक लड़की के साथ नोयडा में छेड़छाड़ शुरु कर दी। युवती के विरोध करने पर हम लोगों ने भी अल्ताफ शेख को छेड़खानी करने से मना किया और उसका किराया वापस कर उसे बस से नीचे उतार दिया था। उस समय उसने नवाबगंज में देख लेने की धमकी दी थी। बेइजती से तिलमिलाए मनचले एवं मनबढ युवक अल्ताफ ने रविवार को अपने दर्जन भर साथियों के साथ दिन-दहाड़े बस रोकवा कर हमला बोल दिया।

शिवसेना नाथ नगरी द्वारा महा आरती का किया गया आयोजन

बरेली । बाबा महादेव का पूजन का अगले सोमवार की महा आरती पशुपतिनाथ मंदिर पर होगी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है महानगर प्रमुख विनोद ने बताया कि सभी माताए बहने इस श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर उनका पूजन अर्चन करें और मर्यादित कपड़ों में मंदिरों में प्रवेश करें इस मौके पर कार्यालय प्रभारी राकेश यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय चंद्रा भवानी सेना की जिला प्रभारी अनीता युवा महानगर प्रमुख स्वाति मंडल प्रभारी सुधा शर्मा जिला सचिव जोत कौर महानगर जिला प्रभारी मिथुन चौधरी महानगर प्रमुख विद्यार्थी सेना शिवम जी जिला सचिव विजय जी जिला उपाध्यक्ष विश्व प्रताप जिला उपाध्यक्ष नवीन शर्मा जी नितेश जी जिला उपाध्यक्ष अंकुर अग्निहोत्री आईटी प्रभारी शिवम मिश्रा शिवम श्रीवास्तव जिला प्रचारक विजय बाबू गुप्ता वरिष्ठ युवा जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा महासचिव संजय चंद्रा युवा महानगर सचिव प्रत्यूष युवा कार्यकारिणी सदस्य रानू सिंह मोहित चंद्र विनोद सिंह आदि सैकड़ो शिव सैनिक उपस्थित रहे।

हाउस टैक्स नगर निगम द्वारा बढ़ाने को लेकर सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने महापौर का किया घेराव

बरेली। नगर निगम के मनमानी हाउस टैक्स के संबंध में पार्षद राजेश अग्रवाल सैकड़ो करदाताओं को लेकर नगर निगम पहुंचे, भीड़ के कारण नगर निगम का बरामदा पूरी तरह भर गया, सबसे पहले उन्होंने नगर आयुक्त से बात की उसके बाद महापौर से मिले,राजेश अग्रवाल ने दोनों ही लोगों को अवगत कराया की जो निगम का पुराना करदाता GIS सर्वे के अंतर्गत अपना टैक्स जमा नहीं करना चाहता है उसे नगर निगम स्वकर का फॉर्म तो दे रहा है लेकिन बैंक का नाम और खाता संख्या फार्म पर प्रिंट नहीं है यह तय हुआ कि उपभोक्ता को बैंक के नाम ब अकाउंट नंबर सहित स्वकर का फॉर्म दिया जाए और उपभोक्ता सीधे बैंक में अपने कर की गणना कर बैंक में जमा कर सकता है। इस तरह से पुराने करदाताओं को नगर निगम के GIS सर्वे से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा बिंदु मिश्रित भावनो के आवासीय भाग पर मिलने वाली छूट नगर निगम ने समाप्त कर दी है, वह अब फिर से मिलने लगेगी लेकिन करदाता को व्यवसायिक का अलग फॉर्म और आवासीय का अलग फॉर्म भरना होगा,। आपको बता दें पूर्व मैं नगर निगम ने आवासीय भवन पर भी छूट पूर्णता समाप्त कर दी थी जो हम लोगों के संघर्ष से मिलने लगी थी, 23/24 का एरियर जो नगर निगम ले रहा था वह भी समाप्त करवा दिया था, राजेश अग्रवाल ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता बत्स से कर विभाग में वहारी व्यक्तियों की तैनाती को समाप्त करने की मांग रखी

और दूसरे विभाग के कर्मचारी जो अपने पद से ऊपर कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य मुक्त करने की बात रखी नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज के प्रदर्शन से जनता को नगर निगम के गलत GIS सर्वे से बहुत अधिक राहत मिलेगी और मिश्रित संपत्तियों पर मिलने वाली छूट पहले की तरह फिर से मिलने लगेगी ।

प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच, बरेली ट्रेड यूनियन, बरेली संघर्ष समिति, बरेली सिविल सोसाइटी का भी योगदान रहा। प्रदर्शन में राजेश अग्रवाल पार्षद संजय आनंद, संजीव मल्होत्रा, जितेंद्र मिश्रा, मुकेश कुमार, राज नारायण, गोहर अली, सुमन मेहरा, नावेद बेग, राजीव मोहन, नासिर अली, मुकेश झा, रोहित राजपूत, राममिलन यादव, अरुण शर्मा, अरविंद अग्रवाल, फुरकान समसी, प्रथमेश गुप्ता, मनीषा, आईएस भिन्डर, मेहताब भाई, मुकेश खटवानी, मुकेश अग्रवाल, दिनेश दद्दा, शिरीष गुप्ता, बॉबी अग्रवाल, राजेश भाटिया, जुबेर समसी, राकेश गुप्ता, महेश यादव, दिलीप, अश्वनी यादव, सलीम खान, डब्बू, मुशाहिद, सिंपल कनौजिया, जफर समसी, छेदा लाल लोधी, जयप्रकाश राजपूत पार्षद, संदीप अग्रवाल, कमल सक्सेना, विजय सिंघल, अमोल शर्मा, मेजर रेहान ,विजय कुमार, सत्येंद्र शास्त्री, संजीव खुराना, इफ्तिखार गुलशन नंदा शिरोज खान संजय कंडारी आदि प्रमुख थे।